



जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 16 महीने बाद मुलाकात

पीएम मोदी को देखकर सीट से खड़े हो गए ट्रंप

एवियन। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को लगभग 16 महीनों बाद जी-7 शिखर सम्मेलन में आमने-सामने की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर थोड़ी देर बातचीत भी की। दोनों नेताओं की आमने-सामने की पिछली मुलाकात वाशिंगटन में पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी। फ्रांस के शहर एवियन-लेस-बॅस में इस वर्ष जी-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर एवियन पहुंचे। यह तब समिट में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवां मौजूदगी है, जो वैश्विक चर्चाओं में भारत की बढ़ती



भूमिका को रेखांकित करती है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम उच्च-स्तरीय कूटनीतिक मुलाकातों से भरा हुआ है। वह कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और, श्व के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत शामिल है। इन मुलाकातों में संबंधों को मजबूत करने और अहम क्षेत्रीय व

वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। शाम को वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित गाला डिनर में अन्य विश्व नेताओं के साथ शामिल होंगे।

इस समिट के एजेंडे में ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों और व्यापक जियोपॉलिटिकल

घटनाक्रमों पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। उम्मीद है कि नई दिल्ली इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उजागर करने और विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ज्यादा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करेगी।

मार्को ने किया था भारत का दौरा

पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक शुल्कों और बयानों को लेकर कुछ तलखी चल रही थी, जिसे सुधारने के लिए हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत का दौरा भी किया था। लेकिन पिछले ही हफ्ते ओमान के तट के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों में एक

नया तनाव पैदा हो गया है। ऐसे गंभीर माहौल और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों के बीच, बुधवार को होने वाली इस द्विपक्षीय वार्ता पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं, जहां पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर अन्य कई विश्व नेताओं के साथ भी बैठकें करेंगे।

समुद्री सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की यह मुलाकात एक बेहद संवेदनशील और जटिल भू-राजनीतिक माहौल के बीच हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका की ओर से लागू की गई नाकेबंदी ने भारत के वाणिज्यिक हितों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन ने भारत को एक सीधा और मजबूत मंच दिया है।

आधार का इस्तेमाल केवल पहचान तक सीमित रहे: सुप्रीम कोर्ट



नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई कर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत के चुनाव आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में करे, न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर इसका उपयोग किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सहमति जताकर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 स्पष्ट रूप से कहती है कि आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। यूआईडीएआई के अपने दिशानिर्देश भी स्पष्ट करते हैं कि आधार केवल पहचान का सबूत है, न कि नागरिकता, पते या जन्मतिथि का सबूत है। इसके बावजूद, यह दस्तावेज व्यापक रूप से स्कूल में दाखिले, प्रॉपर्टी के लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नए वोटर रजिस्ट्रेशन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उम्र,

निवास, नागरिकता और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया। याचिकाकर्ता ने नए वोटर रजिस्ट्रेशन में जन्मतिथि और निवास के लिए आधार के उपयोग को विशेष रूप से चुनौती दी है, इस आधार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ बताया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार नामांकन फ़ेमवर्क के तहत, भारत में करीब 182 दिनों से रह रहे विदेशी नागरिक भी आधार प्राप्त करने के हकदार हैं। आरोप है कि इस ढीले वेरिफिकेशन सिस्टम का फायदा उठाकर कथित घुसपैठिए और अवैध प्रवासी आधार कार्ड पा लेते हैं। वे बाद में इन आधार कार्डों का उपयोग राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर पहचान पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया आधार अधिनियम के तहत स्थापित पहचान फ़ेमवर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और अयोग्य लोगों को सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करती है, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और वास्तविक लाभार्थियों को वंचित होना पड़ता है।

पेपर लीक रोकने के लिए 22 जून तक नहीं चलेगा टेलीग्राम

नयी दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर इस्टेंट मैसैजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी पाबंदी लगा दी है। यह कदम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उठाया है। सरकार के इस निर्णय के बाद कोई भी उपभोक्ता 22 जून तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी मैसैज को एडिट भी नहीं कर पाएंगे।

एनटीए ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले गिरोह कथित तौर पर नीट उम्मीदवारों की ठगने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और पेपर लीक होने के झूठे दावे करते थे। एनटीए के अनुसार



भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एनटीए और राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स को बंद करवाने में मदद की है। एनटीए ने बताया है कि एक-एक करके चैनलों पर कार्रवाई करने से भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होने पर प्लेटफॉर्म-स्तर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।

एनटीए के मुताबिक पेपर लीक और री-एजाम 2026 जैसे नामों वाले चैनलों ने कथित तौर पर नकली पेपर के लिए उम्मीदवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपये की मांग की।

एनटीए ने दावा किया है कि टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर की वजह से एडमिन पुरानी फाइलों को बदलकर उनकी जगह नयी फाइलें डाल सकते थे, जबकि ऑरिजिनल टाइमस्टैम्प वही रहता था। इस वजह से परीक्षा के बाद गुमराह करने वाले सबूत बन जाते थे। एनटीए ने कहा है कि इस निर्णय से असली उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे लेकिन यह सिर्फ परीक्षा की अवधि तक ही लागू रहेगी और इसका मकसद परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना है। एनटीए ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि 21 जून 2026 को होने वाली पुनर्परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। इसके साथ ही एनटीए ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे सिर्फ एनटीए की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत सुरेंद्र दास जी महाराज, शदाणी दरबार से श्री उदय लाल जी तथा कबीर आश्रम सोनपैरी के श्री देवकर साहब जी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर संत-महात्माओं ने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं नैतिक शिक्षा से जुड़े पारंपरिक श्लोकों और मंत्रों को पुनः शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर में चोरी की जांच कराई जाए: मिश्रा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की रकम बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने के मामले में भाजपा और संघ परिवार पर तीखा हमला करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस घपले की समयबद्ध जांच करा दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। पार्टी ने राम मंदिर के चंदे में भारी



हेर फेर से लेकर दान राशि की चोरी के ताजा मामले का हवाला देते हुए यह आरोप भी लगाया है कि इसमें 1400 करोड़ रुपए से अधिक की सुनियोजित लूट हुई है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे से चोरी-गबन के खुलासे से गरमाए विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश के अपने दो शीर्ष नेताओं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तथा विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा मोना को मंगलवार को मैदान में उतारा। अजय राय और अराधना मिश्रा ने यहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा-आरएसएस पर करोड़ों रामभत्तों का आस्था के साथ बड़ा छल और धर्म के नाम पर संगठित लूट को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जांच के लिए गठित एसआईटी पर अविश्वास जताया।

भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने उठाएं प्रधानमंत्री: प्रियंका

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तीन भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे (अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मामला) को उठाना चाहिए।



उन्होंने इस बात पर हैरानी जाहिर की है कि अभी तक इस मामले पर सरकार ने खुलकर कोई बात ही नहीं की है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने तीन भारतीय नाविकों की मौत का मामला उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह हैरानी की बात है कि जो हो रहा है, उस पर सरकार ने आज तक खुलकर कोई बात ही नहीं की है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कि अमेरिका ने एमटी सेटबेलो जहाज पर हमला करके तीन भारतीय नाविकों की क़त्ल हत्या कर दी। भारतीय नाविक सवार हैं, बावजूद इसके उसने हमला किया।

डीजल, विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा

नयी दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें



16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है। इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किया गया था। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा खासी का सिरप

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत देश भर की फार्मसियों से कफ सिरप समेत किसी भी तरह का सिरप खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद, ये दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। ऐसे सिरप खरीदने के लिए ग्राहकों को अब रजिस्टर्ड डॉक्टर की लिखी हुई वैलिड पर्ची दिखानी होगी। 9 जून, 2026 का यह नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर लोगों की राय की समीक्षा करने के बाद जारी किया गया था। इस बदलाव के तहत, सरकार ने ड्रग्स रूल्स के शेड्यूल च में शामिल दवाओं की कैटेगरी से सिरप शब्द हटा दिया है। इस बदलाव से सिरप की बिना पर्ची वाली बिक्री खत्म हो जाएगी और वे ज्यादा सख्त रेगुलैटरी नियमों के दायरे में आ जाएंगे, जिसके लिए उन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, इन नियमों को ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

सनत जैन

ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता सफल हुई, अब शुरुवार अर्थात् जुम्मे के दिन समझौते पर हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है। इस समझौते को लेकर सारी दुनिया के देशों में एक सुखद प्रतिक्रिया देखने की मिली है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया इस समझौते को लेकर ना वाली है। जिसके कारण ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर होने के पहाले ही विवादों में फंस गया है। ऐसा लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन दिनों शनि, राहु और केतु की क़र्रूढ़ दृष्टि है, जिसके कारण वह जो सोचते हैं ठीक उसके विपरीत होता है।

समय और काल का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में रहता है, यही कारण है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को यह दिन देखना पड़ रहे हैं। वह ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने के लिए अभी तक कई प्रयास कर चुके हैं। 40 बार से अधिक दफा झूठ बोल चुके हैं। उसके बाद भी वह इस युद्ध की विभीषिका से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाल ही में जी7 के सम्मेलन में भी उन्हें अपने सहयोगी देशों से सहयोग नहीं मिला, जिसकी वह आशा करके जी7 के सम्मेलन में गए थे। जिस तरह से निकाह में लड़की से पूछा जाता है कि तुम निकाह के लिए राजी हो या नहीं, इस अवसर पर काजी उपस्थित रहता है लड़की यदि हां कर देती है, इसके बाद

काजी साहब निकाह की रस्म अदा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समझौते पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हां नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि शांति समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास किए गए थे वह सब निष्फल होते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल स्वतंत्र राष्ट्र है इस पर यह समझौता लागू नहीं किया जा सकता है। इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रह दशा इन दिनों बड़ी खराब चल रही है। उनके साथ उनके ही विश्वासपात्र लोग विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसी



स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं वह करें तो क्या करें। ईरान जैसा देश जिसके ऊपर अमेरिका और यूरोप के देशों ने पिछले 47 वर्षों से तरह-तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे ईरान हर प्रतिबंध को झेल रहा था। उसने कभी किसी के ऊपर, कोई हमला नहीं किया। वह अमेरिका के खिलाफ ऐसा लड़ेगा यह तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा था। फरवरी माह से जो युद्ध शुरू हुआ था उसकी परिणति इस रूप में

होगी यह ना तो अमेरिका ने सोचा था ना ही इजराइल ने सोचा था। इस सारे विवाद में ईरान की जैसे लॉटरी खुल गई है। ईरान की जो संपत्तियां जप्त की गई थीं, ईरान के जो पैसे जप्त किए गए थे, उन सबको लौटाने की जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी के देशों पर डालना चाहते हैं। अरब देशों की रक्षा अमेरिका नहीं कर पाया, अब सब ईरान के साथ सहयोग करके अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है, कि यूएई ने भी ईरान के साथ समझौता कर लिया है। ऐसी स्थिति में ईरान की किस्मत पलट गई तो पिछले 4 दशकों से ईरान की जनता ने जो दुख भोगे थे वह अब खत्म होने की कारार पर आ गए हैं। ईरान के अच्छे

दिन अब शुरू हुए हैं। इजराइल के खराब दिन अब शुरू होना प्रारंभ हो गए हैं। इस युद्ध में इजराइल में जो बर्बादी हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जो सोचा था। ठीक उसके विपरीत परिणाम देखने को दोनों को मिल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों की मति खराब हो गई है, जब उन्हें मिलकर निर्णय करना था उस समय वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इससे दोनों को नुकसान होना तय है। फिलिस्तीन और गाजा में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो नरसंहार किया था। महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से मारा गया था। लगातार है उन सभी की बददुआ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लग रही है। उनके

भगवान भी अब उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। लगता है जो कर्म किए थे अब उनके फल मिलना दोनों को शुरू हो गए हैं। बहरहाल ईरान के जहां अच्छे दिन शुरू होते हुए दिख रहे हैं वहीं सारी दुनिया को इस लड़ाई से एक संदेश भी मिल रहा है अति सर्वत्र वर्ज्येत। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जब वह अहंकारी हो जाता है, जनता को कष्ट और दुख देने लगता है, अपने आप को भाग्य विधाता मानने लगता है तब जो हाल वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के हो रहे हैं वही होता है। भारत में भी इसके सेकड़ो उदाहरण हैं। अभी ऐसा लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो गया है सारी दुनिया में जो भय और आतंक फैला हुआ था।

संक्षिप्त समाचार

पंचायत विभाग में फेरबदल: 27 जनपद सीईओ के बदले प्रभार
रायपुर । पंचायत-ग्रामीण विकास विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। मंत्रालय स्थित महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार राज्य की 27 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) के प्रभार में परिवर्तन किया गया है। इस फैसले के बाद कई जिलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना तय की गई है। जारी आदेश के तहत बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, दुर्ग, राजनांदागंव, बेमेतरा और गुंगेली समेत विभिन्न जिलों के जनपद पंचायत सीईओ का तबादला किया गया है। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जबकि कई को अन्य जिलों में पदस्थ किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक यह फेरबदल पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की निगरानी बेहतर हो और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव के बाद पंचायत विभाग की कार्यशैली और विकास कार्यों की रफ्तार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

पिंक पेट्रोल की तटपरता से बिछड़ा मासूम अपनी मां से मिला

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में संचालित पिंक पेट्रोल यूनिट द्वारा मानवीय संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए एक बिछड़े हुए मासूम बच्चे को उसकी मां से सुरक्षित मिलाया गया। दिनांक 16/6/2026 को मरही माता मंदिर पॉइंट के पास मध्य जग के पिंक पेट्रोल यूनिट को लोगभग 4-5 वर्ष का एक बालक लावारिस अवस्था में रोते हुए मिला। टीम द्वारा बच्चे को सुरक्षित रोककर उससे पूछताछ की गई। पृच्छने पर बच्चे ने अपना नाम आराध्य गुप्ता बताया, किंतु वह घबराया हुआ होने के कारण अपनी मां एवं अन्य जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। पिंक पेट्रोल यूनिट द्वारा बच्चे को साथ लेकर आसपास के क्षेत्र में उसकी मां एवं परिजनों की तलाश की गई। लगातार खोजबीन एवं पूछताछ के दौरान बच्चे की मां पिंकी गुप्ता, पति स्वर्गीय राजेश गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, निवासी भैरव नगर, संतोषी नगर, रायपुर, मेकाहारा परिसर के अंदर मिली, जो अपने बच्चे को दूढ़ रही थी। महिला ने बताया कि वह अपने इलाज के लिए मेकाहारा आई हुई थी। इसी दौरान भीड़-भाड़ में उसका बच्चा हाथ छुड़ाकर कहीं चला गया था, जिसकी वह पिछले लगभग 3-4 घंटे से तलाश कर रही थी। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। बच्चे द्वारा महिला को अपनी मां के रूप में पहचानने एवं आवश्यक पृष्ठि के उपरांत पिंक पेट्रोल टीम द्वारा बालक आराध्य गुप्ता को सक्षुशल उसकी मां के सुपुर्द किया गया। अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर महिला ने रायपुर पुलिस एवं पिंक पेट्रोल टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है।

छत्तीसगढ़ में बदले संपत्ति बिक्री के नियम! बिना ई-टेंडर नहीं बिकेंगी नगर पालिका की जमीन-दुकानें

रायपुर। नगरीय निकायों की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री और अधिकार देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम, 2026 लागू कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों का उद्देश्य निकायों की संपत्तियों के उपयोग, आवंटन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना

जून आधा बीता फिर भी गर्मी बरकरार, प्रदेश में अगले 5 दिन कई इलाकों में बरसेंगे बादल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। जून का आधा महीना बीतने के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। रायपुर समेत मध्य क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 39 से 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। कुछ इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं से राहत मिलने की संभावना जताई गई है।



द्रोणिका के असर से इन इलाकों में हुई बारिश:- मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में बनी द्रोणिका के प्रभाव से सरगुजा संभाग

के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। सोमवार को सूरजपुर जिले के ओड़गी में सबसे ज्यादा 5 सेमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं रामानुजनगर, प्रतापपुर और

जशपुर जिले के कांसाबेल में 2-2 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा बलरामपुर, कोरबा के पाली और करतला, बलौदाबाजार के गिधौरी दुंड्रा, सूरजपुर के प्रेमनगर और रायगढ़ के मुकडेगा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई।

प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू स्कूल के पहले दिन विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया गया स्वागत

रायपुर। प्रदेश में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों का शिक्षकों ने तिलक लगाकर और किताबें भेंट कर स्वागत किया। स्कूलों में बच्चों के चेहरों पर उत्साह और नई उम्मीदें साफ नजर आईं। खासकर पहली बार स्कूल पहुंचे नौनिहालों के लिए यह दिन यादगार रहा। छत्तीसगढ़ नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 जून तक चलेगा। इस दौरान नए विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाला प्रवेश उत्सव का मुख्य समारोह 30 जून को आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव मासूम बच्चे को उसकी मां से सुरक्षित मिलाया गया। दिनांक 16/6/2026 को मरही माता मंदिर पॉइंट के पास मध्य जग के पिंक पेट्रोल यूनिट को लोगभग 4-5 वर्ष का एक बालक लावारिस अवस्था में रोते हुए मिला। टीम द्वारा बच्चे को सुरक्षित रोककर उससे पूछताछ की गई। पृच्छने पर बच्चे ने अपना नाम आराध्य गुप्ता बताया, किंतु वह घबराया हुआ होने के कारण अपनी मां एवं अन्य जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा था। पिंक पेट्रोल यूनिट द्वारा बच्चे को साथ लेकर आसपास के क्षेत्र में उसकी मां एवं परिजनों की तलाश की गई। लगातार खोजबीन एवं पूछताछ के दौरान बच्चे की मां पिंकी गुप्ता, पति स्वर्गीय राजेश गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, निवासी भैरव नगर, संतोषी नगर, रायपुर, मेकाहारा परिसर के अंदर मिली, जो अपने बच्चे को दूढ़ रही थी। महिला ने बताया कि वह अपने इलाज के लिए मेकाहारा आई हुई थी। इसी दौरान भीड़-भाड़ में उसका बच्चा हाथ छुड़ाकर कहीं चला गया था, जिसकी वह पिछले लगभग 3-4 घंटे से तलाश कर रही थी। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। बच्चे द्वारा महिला को अपनी मां के रूप में पहचानने एवं आवश्यक पृष्ठि के उपरांत पिंक पेट्रोल टीम द्वारा बालक आराध्य गुप्ता को सक्षुशल उसकी मां के सुपुर्द किया गया। अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर महिला ने रायपुर पुलिस एवं पिंक पेट्रोल टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है।

छत्रों को यूनिफॉर्म, किताबें और साइकिल की सौगात

छत्तीसगढ़ नया शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के लिए कई सुविधाएं लेकर आया है। संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पात्र विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें और साइकिलों का वितरण किया जाएगा। जोड़ना और बेहतर पढ़ाई का वातावरण सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से उपलब्ध कराना है।



स्कूलों ने कर ली थी पूरी तैयारी
छत्तीसगढ़ नया शिक्षा सत्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन ने पहले से तैयारियां पूरी कर ली थीं। स्कूल परिसर की सफाई, कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त किया गया ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके।

सांस्कृतिक विरासत और रायपुर में तिलक और किताब देकर किया गया स्वागत
छत्तीसगढ़ नया शिक्षा सत्र के पहले दिन राजधानी रायपुर के स्कूलों में विशेष आयोजन देखने को मिला। स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों का शिक्षकों ने तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें नई किताबें दी गईं। खासकर पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखने वाले छोटे बच्चों के लिए यह पल बेहद खास और यादगार बन गया।

साइकिलों का वितरण किया जाएगा। जोड़ना और बेहतर पढ़ाई का वातावरण सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से उपलब्ध कराना है।

सीजीएमसी पंजीयन नियम में बदलाव

बिना स्थानीय रजिस्ट्रेशन के डॉक्टरों की इजाजत पर सवाल

रायपुर। प्रदेश में चिकित्सकीय प्रैक्टिस से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव अब विवाद का केंद्र बन गया है। राज्य में बाहर से आने वाले एलोपैथी डॉक्टरों के लिए सीजीएमसी (छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल) में पंजीयन की अनिवार्यता को लेकर जारी नए आदेश के बाद चिकित्सा समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। डॉक्टरों और मेडिकल छात्र संगठनों ने इस फैसले को स्थानीय रोजगार और चिकित्सा व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के आधार पर सीजीएमसी ने नई अधिसूचना लागू की है। इसके अनुसार अब अन्य राज्यों के एलोपैथी डॉक्टरों को राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए केवल निर्धारित प्रक्रियाओं और उनके स्वप्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) के आधार पर ही अनुमति मिल



सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कई मामलों में अब स्थानीय स्तर पर विस्तृत पंजीयन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं रहेगी। इसी प्रावधान को लेकर राज्य के चिकित्सा संगठनों में असंतोष तेजी से बढ़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह फैसला न केवल नियामक व्यवस्था को कमजोर करता है बल्कि स्थानीय चिकित्सकों के अवसरों पर भी असर डाल सकता है। छत्तीसगढ़ में सीजीएमसी पंजीयन नियमों में बदलाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और

स्थानीय अधिकारों को लेकर विवाद खड़ी कर दी है। डॉक्टर संगठनों के विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बाद मामला अब सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक टकराव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस अधिसूचना का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में पहले से ही मेडिकल स्नातक, पंजीयन नियमों में बदलाव ने इंटर्न और जूनियर डॉक्टर सीमित पदों, भर्ती में देरी और कार्य

नर्सिंग स्टाफऔर पैरामेडिकल कर्मी प्रभावित
डॉक्टर संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस नीति का प्रभाव केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं रहेगा। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों के रोजगार अवसर भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। उनका कहना है कि नियमों में ढील देने से स्थानीय लोगों की भर्ती पर सीधा असर पड़ेगा। इससे राज्य

परिस्थितियों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में बाहरी राज्यों के डॉक्टरों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाना स्थानीय युवाओं के हितों के खिलाफ है। संगठनों का तर्क है कि यह निर्णय राज्य के हजारों चिकित्सकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और रोजगार अवसरों में असंतुलन पैदा कर सकता है। इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य नीति और नियामक ढांचे को लेकर नई

आंदोलन की चेतावनी
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रेशम सिंह, जेएनएम मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. पीयूष श्रीवास्तव और सीजीडीएफ के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो गम्यत्याती आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर संगठनों ने साफकहा है कि अगर उनके अधिकारों और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ।

परेशानी खड़ी कर दी है। एक तरफ सरकार का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुगम और उपलब्ध कराना बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय डॉक्टर संगठन इसे अपने हितों पर सीधा असर मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस विरोध के बीच इस नीति पर क्या रुख अपनाती है। क्या इसमें संशोधन किया जाएगा या मौजूदा आदेश को ही आगे बढ़ाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./ यां. ला. म. नलकूप एवं गेट संभाग सकरी, बिलासपुर (छ.ग.)				
दूरभाष (कार्यालय) 07781-252881, (फैकस) 252920 Email-collector.asstttw.narayanapur@gmail.com				
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in				
सिस्टम निविदा क्र. 193060 एवं 193063/निविदा सूचना क्र. 02 एवं 03/ब.ले.लि./2026-27 दिनांक. 12.06.2026				
निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 03.07.2026 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-				
निविदा सूचना क्र	निविदा सिस्टम क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	
02/ब.ले.लि./26-27 दिनांक. 12.06.26	193060 (प्रथम आमंत्रण)	जिला-सुरगेली अंतर्गत निर्मित एनोकर / स्टपडेय के जलद्वारो का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य	145.51 लाख जी.एस.टी. छोड़कर	
03/ब.ले.लि./26-27 दिनांक. 12.06.26	193063 (प्रथम आमंत्रण)	बिलासपुर जिले के विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत लछनपुर व्यक्पनन योजना के जलद्वारों का पेंटिंग तथा सुधार / मरम्मत कार्य, रिमोट कंट्रोल सिस्टम का उन्नयन कार्य तथा कार्यस्थल पर प्रकाश व्यवस्था कार्य।	125.24 लाख जी.एस.टी. छोड़कर	
(निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. दिनांक 22.08.2022 के आधार पर)				
अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्वायरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 19.06.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते हैं।				
नोट :-1. निविदा में भाग लेने हेतु उम्मेदवारों को ई-प्रोक्वायरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उम्मेदवार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। 2. निविदाकार को इस निविदा में वर्ष 2025 में जारी किए गये Pre Bid Qualification certificate (Valid up to 30.09.2026) का उपयोग अनिवार्य है। 3. निविदा पत्र अर्हता के संबंध में निविदा प्रपत्र फार्म बी. के काइंडका 2.1.1 (स.क. 4 एवं 5) एवं एनेक्चर । (पूर्व अर्हता एवं फार्म बी. दस्तावेज) में वर्णित अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें। 4. निविदाकार द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव में जी.एस.टी. छोड़कर निविदा भरा जाता है।				
जी-262701422/10			कार्यपालन अभियंता वि./यां.ला.म.नलकूल एवं गेट संभाग सकरी बिलासपुर (छ.ग.)	

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT	
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER	
MAHANADI PROJECT, RAIPUR (CHHATTISGARH)	
e-PROCUREMENT TENDER NOTICE	
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in (First Call)	
System Tender No. 193185/ NIT No.: 08/SAC/26-27	Dated: 12.06.2026
Online Tenders are invited for the following work up to 03.07.2026 at 17.30 Hours.	
Name of work-Construction of Residential Premises for Employees and other Buildings including Renovation of I-Type Quarters on vacant land near Marine Drive Behind Soil Testing Lab of Water Resources Department, Shanti Nagar in Block Dharsiya, District Raipur.	
Probable Amount of Contract: Rs. 311.85 Lakhs (Excluding G.S.T.)	
(As per S.O.R Enforced from Dated 01.05.2025 and amended on dated 08.08.2025 of C.G. W.R.D., S.O.R Enforced from Dated 01.01.2015 of C.G. P.W.D. Building and S.O.R. Enforced from Dated 01.07.2015 of C.G. P.W.D. E&M).	
The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal (https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 19.06.2026, at 17.31 Hours. (IST) onwards.	
NOTE: All eligible/intrested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-procurement portal (https://eproc.cgstate.gov.in) and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process. Prequalification Certificates issued by Water Resources Department whose validity is upto 30.09.2026 is applicable in this tender.	
Executive Engineer Water Management Division No. 1, Raipur For, Chief Engineer, Mahanadi Project Raipur (C.G.)	
G-262701468/7	

रायपुर में आज बादल और अंधड़ के आसार

राजधानी रायपुर में बुधवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और अंधड़ की संभावना है।



अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

5 दिन तक जारी रहेगा बारिश-आंधी का दौर

मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

बेमेतरा सबसे गर्म, अंबिकापुर में सबसे कम तापमान

प्रदेश में गर्मी का असर लगातार जारी है। सोमवार को बेमेतरा सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में सबसे कम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान में इस अंतर के चलते प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिल रहा है।

इंडिगो में सामान लाना और ले जाना हुआ महंगा

बढ़े हुए शुल्क को ऐसे समझिए

रायपुर। अब हवाई जहाज में सामान लाना-ले जाना महंगा हो गया है। इंडिगो ने पांच जून से नई दरें लागू कर दी हैं। इसके अनुसार 15 किलो से ज्यादा सामान ले जाने पर ज्यादा शुल्क देना होगा। इंडिगो की तरफ से पैकेज बनाया गया है। इसी के आधार पर ही शुल्क देना होगा। घरेलू उड़ान में पहले से निर्धारित 15 किलो तक की छूट के बाद पहले तीन किलो के



सामान पर 975 रुपये लगते थे। अब यात्रियों को 1,650 रुपये देने पड़ेंगे।

175 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क बढ़ाया

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ान में पहले आठ किलो के 3,600 लगते थे, लेकिन अब पांच हजार देने पड़ेंगे। इंडिगो ने 175 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क बढ़ा दिया है। पहले से लागू नियम यात्रा के दौरान यात्री अपने साथ 15 किलो तक का सामान बिना कोई शुल्क के लेकर जा सकता है। ये अभी भी है। सात किलो तक सामान यात्री साथ में ले जाता है। सात किलो से अधिक होने पर सामान को उसी विमान में लगेज बॉक्स में डाला जाता है।

समान होने पर 1,650 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 19 किलो ग्राम होने पर यात्री को 2,750 रुपये देना होगा।

सामान का पैकेज तय किया गया है

इंडिगो की तरफ से सामान का पैकेज तय किया गया है। तीन किलो के लिए 1,650 रुपये, पांच किलो के लिए 2,750 रुपये, 10 किलो के लिए 5,995 रुपये और 40 किलो के लिए 19,200 रुपये लगेंगे। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान आठ किलो के लिए पांच हजार, 15 किलो के लिए 7,500 और 30 किलो के लिए 15,00 रुपये का शुल्क लगेगा।

दो कृषि केंद्रों पर की गई छापामार कार्रवाई

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद एवं बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार सघन निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर गुंगेली के निर्देशाुसार उप संचालक कृषि के नेतृत्व में गठित विशेष जिला निरीक्षण दल ने आज लोरमी एवं पथरिया विकासखंड के दो कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी अनियमितताओं का खुलासा किया।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0)

कमांक 2483/ब.ले.लि./2026,	छुईखदान, दिनांक 11/06/2026
निविदा निरस्तीकरण आदेश	
निविदा सूचना कमांक 02 / ब.ले.लि./2025-26 दिनांक 11.08.2026 निविदा सिस्टम कमांक-173473 (प्रथम आमंत्रण) खैरागढ़-छुईखदान-गणगंडई जिले के विकासखण्ड खैरागढ़ के अन्तर्गत लमती फीडर लघु जलाशय योजना के मुख्य बांध का 990 मी. लंबाई में (अनुमानित) मिट्टी बांध का डिजाइन ड्राइंग एवं निमाण स्थोलेले लंबाई 167 मी. (अनुमानित) स्थोल चैनल लंबाई 1050 मी. (अनुमानित) से संबंधित सभी निर्माण कार्य, 01 नव हेक्स्ट्रस डबल गेट के साथ फीडर नहर के निर्माण से संबंधित सभी कार्य, पुर्वसाइट कार्य (बिल्डिंग कार्य इत्यादि) तथा रोड का निर्माण कार्य, बंड लाईन में में ड्रिलिंग के साथ मिट्टी स्टेटा का अन्वेषण अन्वेषण, डुबान क्षेत्र, बंड लाईन एवं स्थोलेले के साथ स्थोल चैनल एवं नया कार्य का पू-अर्जन प्रकरण तैयार करना एवं कम्लायर्स कराना, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली से वन भूमि प्रकरण एवं पर्यावरण बलीयेंस कराना और सभी प्रकार के अन्य संबंधित कार्य, बांध कार्य पूर्ण होने के पश्चात पांच साल वार्षी ठातु तक पूरे कार्यों का संचालन एवं मरम्मत का कार्य हेतु लम्प सम निविदा कार्य, (लागव राशि र.137.23 करोड़) के लिये आमंत्रित निविदा विस्का का जी.नं.-252602762 है, को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिमलाथ भवन, सेक्टर-19 चर्च ब्लाक, नवा रायपुर, अदल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 4263739/TC/25/4790 नवा रायपुर दिनांक 11/06/2026 में दिये गये निर्देश के परिपालन में उक्त आमंत्रित निविदा निरस्त की जाती है।	
कार्यपालन अभियंता जल संसाधन छुईखदान जिला -कैसीजी (छ.ग.)	
जी-262701440/9	

महाशक्तियों के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक चालबाजी

महेंद्र वेद

चीन के साथ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के कुछ ही दिनों बाद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों की जमकर तारीफ करते हुए, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत कहा और पाकिस्तान-भारत के बीच युद्धविराम सुनिश्चित करने तथा अमेरिका व ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान को सौंपने के लिए भी उनका धन्यवाद किया। पाकिस्तान इस मामले में चीन से आगे निकल गया, क्योंकि चीन को मध्यस्थ की भूमिका नहीं मिली। संघर्ष बढ़ने के कारण सहयोगी की यह भूमिका लंबे समय तक चलने की उम्मीद है। लेकिन पर्दे के पीछे से चीन जो भूमिका निभा रहा है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा सकता है कि यह पाकिस्तान के लिए एक खास पल है, जिसमें वह खाड़ी युद्ध में शामिल बड़ी ताकतों और कई अन्य पक्षों के बीच संतुलन बना रहा है। लेकिन उसे चीन का सहयोगी माना जाता है। उधर शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश एक तरह से पाकिस्तान की ओर लौट आया है। अस्थिर राजनीति और आर्थिक संकट के कारण पाकिस्तान को एक विफल देश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिका और चीन ने उसे पूरी तरह विफल नहीं होने दिया है, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाने के लिए होड़ कर रहे हैं, जो रणनीतिक रूप से दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया के मिलन-बिंदु पर स्थित है। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अपनी चालें चलते हुए, पाकिस्तान ने रूस के साथ भी अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन-पाकिस्तान के रिश्तों की बुराई करना या रूस-पाकिस्तान के संबंधों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन आज की लेन-देन वाली दुनिया में उनके लगातार बदलते रिश्तों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। पाकिस्तान के खाड़ी देशों और तुर्किये के साथ संबंध भी अहम हैं। 1962 के भारत-चीन संघर्ष के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने चीन से संपर्क किया था। वह समझ चुका था कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने मार्च 1963 में हुए एक औपचारिक समझौते के जरिये काराकोरम रेंज में लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर में फैली शक्सगाम घाटी का नियंत्रण चीन को सौंप दिया। यह इलाका भारत विवादित कश्मीर का हिस्सा मानता है। इस कदम ने चीन-पाकिस्तान के संबंधों को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। अगर भारत दोनों के लिए एक साझा खतरा न होता, तो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते बहुत अलग होते। चीन ने इस इलाके में अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। कई दशकों से भारत को लगातार परेशान करने के बाद, उसने चीन-पाकिस्तान इकनामिक कॉरिडोर (सीपीईसी) शुरू किया, जिससे उसे हिंद महासागर तक पहुंच मिल गई। इसे रूस भी हासिल करना चाहता था, लेकिन नाकाम रहा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर मजबूत मौजूदगी की वजह से चीन, खाड़ी क्षेत्र के मौजूदा टकराव में सोधे शामिल हुए बिना भी एक अहम खिलाड़ी बन गया है। ग्वादर में चीन की मौजूदगी से भारत कराची पर वैसा नौसैनिक हमला नहीं कर पाएगा, जैसा उसने 1971 में किया था। ईरान के चाहवार मोरल से हटने के बाद भारत की स्थिति कमजोर हुई है। यह बहुत कम ही देखेंगे कि मिलता है कि दो असमान पक्षों (एक मदद करने वाला और दूसरा मदद पाने वाला, एक कम्युनिस्ट देश और दूसरा धर्म पर आधारित देश) के बीच का रिश्ता न सिर्फ छह दशकों से अधिक समय तक कायम रहा हो, बल्कि उसका बहुत यादा रणनीतिक महत्व भी बन गया हो। दोनों ने हमेशा अपने रिश्तों को सबसे शानदार शब्दों में बर्ण किया है, जैसे आर्यन ब्रदर्स (पक्के भाई)। भारत से मिली सैन्य हार ने इस रिश्ते को और मजबूत किया।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसीलिये गीता के %शानैशनैरूपरमेत% आदेश के अनुसार तरीके से ही धीरे 2 बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

तमोगुणी पुरुषों का सर्वथा बहिष्कार कर दिया जाय, यह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि %प्रवृत्तिरेषा भूताना% इस मनुक्तिके अनुसार संसार में तमोगुणी मनुष्यों की संख्या अत्यधिक है वे बहिष्कृत किये जाने पर और भी उद्‌ग्रह एवं उच्छङ्खल हो जाएंगे और देश में ऐसी अशान्ति फैलेगी कि सदाचारी-समुदाय को जीवन निर्वाह करना भी महाकठिन हो जायगा, अतः ईश्वर ने तमोगुणी मनुष्यों को भी धर्मसूत्र में बौध्दकर अस्तित्व बनाये रखने का आदेश दिया है और मनुष्य समाज में उनका विशिष्ट स्थान रख दिया है। वे लोग पूजन सामग्री तो अपने आचार के अनुसार ही बतावें में लायेंगे, परन्तु किसी न किसी तरह ईश्वर उपासक एवं आस्तिक अवश्य बने

रहेंगे। इसीलिए ऋषियों ने –

यदत्रः पुरुषो लोके तदत्रास्तस्य देवताः

अर्थात् – मनुष्य स्वयं जैसा भोजन खाने वाला हो

वह अपने देव-ताओं को भी वैसा ही प्रदान करता है–

– ऐसा सिद्धांत स्थिर किया है। सो भविष्यपुराण का

कुमारी सुभागा देवी आदि विधान भी देवत्व तामस मनुष्यों से ही सम्बन्ध रखता है। वे उक्त रीति से पूजन कर सकते हैं। शेष वैष्णवी उपसना वाले सदाचारी पुरुष तो विशुद्ध पत्रपुष्पादि से ही पूजन करते हैं – यह प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। तमोगुणी अधिकांशियों के लिए वेद में भी ऐसी तामसी उपसना का उल्लेख मिलता है, यथा – यन्मांसं निपृणामि ते। अन्नमु पशोर्मांसम् । इत्यादि प्रभाण दर्शनीय है। महाशय जी ! आपको यह प्रश्न करते हुये आर्यसमाज को उस मांस पाटी का ध्यान नहीं रहा जो कि नित्यप्रति मांस द्वारा ही निराकार बाबा का पूजन करती

क्रमशः ...



नीरज कुमार दुबे

जी-7 शिखर सम्मेलन इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार का मंच नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का आईना प्रतीत हुआ। फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनके सामने वह यूरोप खड़ा था जो अब आंख मूंदकर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं दिखता। लंबे समय तक टैरिफ की धमकियां, कूटनीतिक दबाव, सार्वजनिक अपमान और अचानक फैसलों का सामना करने के बाद अब यूरोपीय देशों ने यह मान लिया है कि ट्रंप बदलती अमेरिकी सोच का स्थायी चेहरा हैं। यही कारण है कि इस बार जी-7 सम्मेलन पर सबसे गहरी छाया अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरी की रही। देखा जाये तो ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक बेचैनी ने इस सम्मेलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई को लेकर चिंता गहरा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के मोड़ में पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रंप इस सम्मेलन में यह साबित करने पहुंचे कि उनकी आक्रामक और टकराव वाली विदेश नीति परिणाम दे रही है। वह चाहते हैं कि दुनिया अमेरिकी प्रार्थमिकताओं को स्वीकार करे, चाहे मामला व्यापार का हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, सुरक्षा का या फिर चीन को घेरने की रणनीति का। लेकिन इस बार यूरोप का स्वर बदला हुआ है। वह अमेरिका के साथ तो रहना चाहता है, मगर उसकी हर बात पर सिर झुकाने को तैयार नहीं है। देखा जाये तो यूरोप के भीतर यह बदलाव अचानक नहीं आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वर्षों से यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा



के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मैक्रों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह ऐसा समय है जब अमेरिकी, रूसी और चीनी नेतृत्व यूरोप के हितों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए यूरोप को अब जागना होगा और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। हालांकि मैक्रों की रणनीति केवल विरोध की नहीं है। उन्होंने ट्रंप के साथ निजी संबंध बनाए रखने की भी भरपूर कोशिश की है। कभी एफिल टावर पर भोज, कभी सैन्य परेड में विशेष सम्मान और कभी नोटे डेम कैथेड्रल के पुनरोद्धार समारोह में आमंत्रण देकर उन्होंने ट्रंप को साधने की कोशिश की है। लेकिन ईरान युद्ध और ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप में ट्रंप विरोध चरम पर पहुंच गया। एक समय तो हालात ऐसे बन गए थे कि यूरोपीय नेताओं को लगने लगा कि ट्रंप डेमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं। यह केवल एक भू-राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उस भरोसे के टूटने का प्रतीक था जिस पर दशकों से अटलांटिक गठबंधन टिका हुआ था। दरअसल, ग्रीनलैंड प्रकरण ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। यही कारण है कि अब यूरोपीय देशों में यह बहस तेज हो गई है कि

महाराणा प्रताप



राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुण्डली व कालगणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ।[महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननिहाल पाली में था मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में सप्त पंक्तियां में ताम्र पत्र उल्लेखित है। और सोमानी रचित पुस्तक में महाराणा प्रताप द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का उल्लेख है इन स्रोतों से सत्य है की महाराणा प्रताप के ननिहाल की भूमि का उल्लेख पाली का करना उचित है। महाराणा प्रताप के जन्मस्थान के प्रश्न पर दो धारणाएँ हैं। पहली महाराणा प्रताप का जन्म कुम्भलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदयसिंह एवम जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में

हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगर अखेराज की शक्ति बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बिता , भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे , भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिन्दुवा सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदयसिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे।[11] कुम्भलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नही था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत मे सबसे शक्तिसम्पन्न थे। एवं जयवंता बाई के पिता एवम पाली के शाषक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामन्त एवं सेनानायक था। इस

कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ो की कमध्छज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी, अतः उज्जयिन्त बाई को पाली भेजा गया। वि. सं. ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया सं 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदयसिंह की सेना ने प्रयाण प्रारम्भ कर दिया और मावली युद्ध मे बनवीर के विरूद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेन्द्र सिंह शकावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनि कचहरी पाली में विद्यमान है। यहां सोनगरो की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है।

भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका

देवी एम. चेरियन

भारत दुनिया के सबसे विविध लोकतंत्रों में से एक है। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराएं और प्राथमिकताएँ हैं। इसलिए, स्वाभाविक ही है कि स्थानीय आकांक्षाओं और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। इनमें से कई दलों ने उन मुद्दों को उजागर करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन पर शायद राष्ट्रीय नेताओं का पर्याप्त ध्यान नहीं गया हो। साथ ही, भारतीय राजनीति का इतिहास दिखाता है कि कई क्षेत्रीय दल किसी विशेष मुद्दे, किसी लोकप्रिय स्थानीय नेता या किसी मजबूत भावनात्मक आंदोलन से पैदा होते हैं। कुछ क्षेत्रीय पहचान के इर्द-गिर्द उठते हैं, कुछ भाषा के इर्द-गिर्द और अन्य इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके जैसे बड़े और जटिल देश के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी के लिए कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल इतने महत्वपूर्ण हैं।

क्षेत्रीय दल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्थानीय जरूरतों को समझने और अपने राज्यों के हितों की रक्षा करने में है। वे अक्सर बड़े संगठनों की तुलना में अधिक फुलीले होते हैं क्योंकि वे लोगों के करीब रहते हैं और राज्य-विशिष्ट चुनौतियों का तुरंत जवाब देने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति ही ऐसी है कि इसका दायरा सीमित होता है और ज्यादातर यह बहुत परिवार-उन्मुख होती है। भारत जैसे बड़े और जटिल देश के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी के लिए कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल इतने महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय पार्टियां ऐसी संस्थाएँ हैं, जो टिके रहने के लिए बनी हैं। जब केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक सुधार, प्रौद्योगिकी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर

ध्यान केंद्रित करने की स्थिरता होती है, तो क्षेत्रीय दल उस काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जो वे सबसे अच्छा करते हैं-अपने राज्यों के कल्याण और विकास की देखभाल करना। वे स्कूलों, अस्पतालों, उद्योगों, कृषि और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर सकते हैं। सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब राष्ट्रीय सरकार और राज्य लगातार राजनीतिक टकराव में उलड़ने की बजाय मिलकर काम करते हैं। भारत की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं को ठीक इसी तरह के सहयोग की आवश्यकता होती है। राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, औद्योगिक गलियारे, डिजिटल बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी कार्यक्रम, ये सभी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करीबी समन्वय पर निर्भर करते हैं।

दुर्भाग्य से, हाल के वर्षों में राजनीति रचनात्मक होने की बजाय अधिक टकराववादी हो गई है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच का आदान-प्रदान कई बार अनावश्यक रूप से कड़वा हो गया है और राजनीतिक नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अक्सर कठोर और स्थूलक रही है, असहनीय। लोकतंत्र में निश्चित रूप से मजबूत बहस की आवश्यकता होती है लेकिन बहस का रूप अनादर में नहीं बदलना चाहिए। जनता नेताओं से नीति पर असहमत होने की उम्मीद करती है लेकिन फिर भी गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने की चाह रखती है। एक और चुनौती, जिससे भारतीय राजनीति को पार पाना है, वह है जाति, पंथ, धर्म और पहचान-आधारित वोट बैंकों पर निर्भर निर्भरता। यह संकीर्ण रूप से केंद्रित क्षेत्रीय या वर्गीय दलों के उभरने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। जब

लोगों को लगता है कि उन्हें केवल जाति या धर्म के चश्मे से संबोधित किया जा रहा है, तो वे स्वाभाविक रूप से उन दलों की ओर आर्जित होते हैं, जो अस्थायी रूप से उन पहचानों का प्रतिनिधित्व करने का वादा करते हैं। और यही फिर क्षेत्रीय दलों का मजबूत पक्ष बन जाता है, जो थोड़े समय के लिए उनके बहुत फायदे का होता है।



बड़े राष्ट्रीय दलों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे राजनीति की इस शैली से ऊपर उठें। उन्हें मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो लोगों को विभाजित करने की बजाय जोड़ते हैं। राजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसर हर परिवार के लिए मायने रखते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। यही कारण है कि भारत को दो मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक शक्तियाँ और एक स्वस्थ विपक्ष के होने से लाभ मिलता है। एक जीवंत लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो निर्णय ले सके और एक ऐसे विपक्ष की, जो उनसे सवाल कर सके। विपक्ष की भूमिका राजनीति के लिए हर कदम का विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह

बनाना, रचनात्मक विकल्प पेश करना और उन नीतियों का समर्थन करना है, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित में हो।

भारत आज अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले कई वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत को एक उभरती हुई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में वैश्विक

मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का एक दृढ़ और सफल प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, विनिर्माण, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करने पर दिए गए जोर ने एक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी राष्ट्र की छवि बनाने में मदद की है। चाहे कोई हर नीति से सहमत हो या न हो, इस बात की व्यापक मान्यता है कि भारत की वैश्विक स्थिति के निर्माण के लिए निरंतरता, स्थिरता और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। जो देश दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की इच्छा रखता है, वह लगातार राजनीतिक अनिश्चितता या खंडित शासन को सहन नहीं कर सकता। इसे मजबूत राष्ट्रीय संस्थानों के आवश्यकता है जो सक्षम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा कर सकें। यदि भारत मजबूत राष्ट्रीय दलों, सक्रिय क्षेत्रीय नेतृत्व, एक जिम्मेदार विपक्ष और जाति, पंथ, धर्म एवं व्यक्तिगत हमलों से ऊपर उठने वाली राजनीति के साथ एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर सकता है, तो यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत और सम्मानित देशों में से एक बनने की अपनी यात्रा को भी जारी रखेगा, जैसा कि मोदी सरकार सफलतापूर्वक कर रही है।

आज का इतिहास

- 1994 – उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को अपने देश में बने रहने देने को सहमत।
- 1999 – लेकव जुमा द. अफ्रीका के उपराष्ट्रपति नियुक्त, कारगिल में चल रहे युद्ध के महेनजर आई.एस.आई. द्वारा कारगिल जेहाद फ़ंड की स्थापना।
- 2001 – नेपाल शाही परिवार हत्या प्रकरण में डॉक्टर ने कहा कि दीपेन्द्र के खून में शराब का अंश नहीं था।
- 2002 – कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुन् खोला गया।
- 2003 – फ्रांस में 165 ईरानी आतंकवादी गिरफ्तार।
- 2004 – मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते-जुलते पत्थर मिले। बगदाद में सेना की भर्ती केन्द्र पर विस्फोट में 42 मरे तथा 127 घायल। देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान %तेज़स% का बंगलौर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रूस ने 2012 तक अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाला।
- 2012– साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनीं।
- 1973 – लिएंडर पेस – भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी
- 1981 – अमृता राव – हिन्दी चलचित्र अभिनेत्री।
- 1970 – निशिकांत कामत – हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता थे।
- 1945 – पी. डी. टी. आचार्य – भारत के भूतपूर्व लोक सभा महासचिव रहे हैं।
- 1942 – भगत सिंह कोश्यारी – उत्तराखंड के राजनीतिज्ञ तथा वहाँ के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं।
- 1903 – स्वतंत्रता प्रसाद अग्रवाल – असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, ज्योतित्रता सेनानी तथा फिल्म समिति।
- 1887 – कैलाश नाथ काटजू – प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री।
- 2015 – मदन मोहन पंजे – भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश थे।
- 1928 – गोपबंधु दास – प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता।
- 1895 – गोपाल गणेश आगरकर – प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता।
- 1862 – लॉर्ड कैनिंग – भारत के पहले वाइसराय और कुशल राजनीतिज्ञ
- 1858 – रानी लक्ष्मीबाई – 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरंगना रानी।

जी-7 शिखर सम्मेलन- दुनिया जता रही मोदी पर भरोसा

सार्वजनिक कर उन्होंने यह दिखा दिया था कि यूरोपीय नेता निजी तौर पर अमेरिका के दबाव को स्वीकार करते हैं, भले ही सार्वजनिक मंचों पर विरोध का अभिनय करें। इस कारण अब यूरोपीय नेताओं के लिए संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट रखना है और अमेरिका से रिश्ते भी नहीं बिगाड़ने हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सम्मेलन में विशेष महत्व रखती है। जब पश्चिमी दुनिया भीतर से विभाजित दिखाई दे रही है, तब भारत एक ऐसे संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है जिस पर हर शक्ति केंद्र भरोसा करना चाहता है। मोदी ने रूस और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखे, पश्चिम एशिया के संकटों में संतुलन साधा और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिर नेतृत्व वाली निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है।

देखा जाये तो मोदी की कूटनीति को सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने भारत को किसी एक खेमे में सीमित नहीं होने दिया। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी कायम रखी और रूस के साथ पुराने रिश्ते भी नहीं टूटने दिए। पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकार्यता बनी रही और यूरोप के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग भी लगातार बढ़ता गया। जी-7 जैसे मंचों पर मोदी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत केंद्र में आ चुका है। जब दुनिया अविश्वास, टकराव और अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत संवाद, संतुलन और स्थिरता का चेहरा बनकर उभरा है। यही प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहरहाल, जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गहरे मतभेदों

और पश्चिमी देशों के भीतर बढ़ती अविश्वास की राजनीति के बावजूद संवाद की प्रक्रिया टूटी नहीं। ईरान संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हुए तनाव, तेल आपूर्ति को लेकर आशंकाओं और यूक्रेन युद्ध की लंबी खिंचती स्थिति के बीच सदस्य देशों ने कम से कम इस बात पर सहमति दिखाई कि बहुपक्षीय सहयोग को जिंदा रखना जरूरी है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और विकासशील देशों के कर्ज संकट जैसे मुद्दों पर साझा चर्चा आगे बढ़ी। यूरोप ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का स्वर बुलंद किया, जबकि अमेरिका ने भी यह संकेत दिया कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों में अधिक भागीदारी निभानी होगी। भारत, ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भागीदारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल साउथ को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों की आकांक्षाओं को मजबूती से उठाकर भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया। हालांकि सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर ठोस नतीजे देने में विफल भी रहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई निर्णायक रोडमैप सामने नहीं आया, चीन को लेकर पश्चिमी देशों के भीतर मतभेद बने रहे और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय को जानबूझकर पीछे कर दिया गया ताकि अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव नहीं बढ़े। ईरान समझौते पर भी स्पष्टता का अभाव रहा और ट्रंप की आक्रामक शैली के कारण साझा घोषणापत्र को अनिश्चितता से जूझ रही है। यहां संवाद तो जारी रहा लेकिन भरोसे का संकेत अब भी गहराता दिखाई दिया।

पंडित नेहरू के इंडिया से मोदीजी के भारत तक



हरदीप सिंह पुरी

मोदीजी ने 10 जून, 2026 को प्रधानमंत्री के पद पर अपना लगातार 4399वां दिन पूरा कर लिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1952 में पहली निर्वाचित सरकार से 1964 में उनके निधन तक लगातार प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया। 1947 से देखें तो सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड अब भी पंडित नेहरू के नाम ही है। लेकिन मोदीजी ने उन्हें हमारे गणराय के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित शासन प्रमुख रहने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस दरमियान मैंने अपना कामकाजी जीवन शासन के अंदर गुजारा है। इस उपलब्धि में मेरी दिलचस्पी गणित के लिहाज से कम है। मेरी यादा दिलचस्पी इसमें है कि इस उपलब्धि को कैसे मापा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया है कि सरकार को इस बात से आंका जाना चाहिए कि कतार के आखिर में खड़े आदमी तक क्या कुछ पहुँचता है। इसे ही अंत्योदय कहते हैं। पंडित नेहरू के ‘इंडिया’ और मोदीजी के ‘भारत’ के बीच का फासला वह दूरी है जिसे इस आखिरी आदमी ने तय किया है। एक निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो

देखते हैं कि पंडित नेहरू को विरासत में क्या मिला था। उन्हें विरासत में एक ऐसा विभाजित उपमहाद्वीप मिला जो इतिहास के सबसे बड़े जबरन विस्थापन से जूझ रहा था, दो सदियों के औपनिवेशिक शोषण से खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था मिली, ऐसी आबादी मिली जिसमें पाँच में से एक से भी कम लोग पढ़-लिख सकते थे और औसत उम्र तीस साल के आस-पास थी। उस विरासत के आधार पर उन्होंने एक ऐसा संवैधानिक लोकतंत्र खड़ा किया जो टिका रहा, जबकि एक के बाद एक स्वतंत्र हुए कई अन्य देश सेना के जनरलों या तानाशाहों के कब्जे में चले गए (योजना आयोग दिशा तय करता था, सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ थी और लाइसेंस प्रणाली यह तय करती थी कि कौन क्या उत्पादन कर सकता है। विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएँ, परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम–आजाद भारत की संस्थागत नींव उन्हीं वर्षों में रखी गई थी।मैं 1974 में विदेश सेवा में आया और जिस भारत का मैंने प्रतिनिधित्व किया, वह एक गंभीर देश था जिसने अपनी व्यवस्था की क्षमता के अनुसार पूरी गरिमा के साथ अभावों का सामना करने का रास्ता चुना था। उस व्यवस्था की कीमत तब तक साफ दिखने लगी थी जब तक मैं अपने करियर के मध्य पड़ाव पर पहुँचा। सरकार ने योजनाओं का आवंटन करना तो सीख लिया था, लेकिन वह

वितरण करना नहीं सीख पायी थी। दिल्ली में घोषित किसी योजना और गाँव में मिलने वाले लाभ के बीच का जो फासला था, वहीं सारा पैसा गायब हो जाता था। एक पूर्व प्रधानमंत्री का यह मानना कि हर एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह पैसे ही गरीबों तक पहुँच पाते हैं, इस मॉडल पर अपने आम में एक बड़ा सवाल था। सरकार योजना तो बना सकती थी, लेकिन वह लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी।

2014 में मोदी जी को जो विरासत मिली, उसका भी उतना ही ईमानदार मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कमान संभाली थी जिसे बाज़ार ने परेज़ाइल फाइव (पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) की श्रेणी में रखा था; जो अटकी हुई परियोजनाओं के बोझ तले दबी थी, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार से घिरी थी जिसने शासन से जेनता के भरोसे को ही खोखला कर दिया था। इसका समाधान उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था बनाकर किया। योजना आयोग’ की जगह नीति आयोग ने ले ली, जो रायों की निर्देश देने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलता है। पहचान (पहचान पत्र), बैंक खाता और मोबाइल फोन को एक साथ जोड़ा गया और सरकार ने बिचौलियों के बजाय, जो चार दशकों से अपना कमीशन ले रहे थे, नागरिकों को सीधे भुगतान करना शुरू कर दिया।प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एक

निर्णायक माध्यम है जो बहुत साधारण लगता है लेकिन इसने शासन के इरादे की बजाय वास्तविक लाभ के मिलने पर ध्यान केंद्रित किया।

इसके बाद जो हुआ, वह एक मंच के रूप में सरकार की नई परिकल्पना थी। भारत ने सार्वजनिक डिजिटल ढांचा और एक ऐसी पहचान व्यवस्था बनाई जो पूरे उपमहाद्वीप में काम करती है। एक ऐसा भुगतान नेटवर्क खड़ा किया गया जिसका आज पूरी दुनिया अध्ययन कर रही है। पचास करोड़ से अधिक जनधन खातों ने उन परिवारों के लिए औपचारिक बैंकिंग के दरवाजे खोल दिए, जहाँ यह सुविधा पहले कभी नहीं पहुँची थी।नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, इसी दशक में लगभग पचीस करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और जिस अर्थव्यवस्था को बाजारों ने खारिज कर दिया था, वह अब किसी भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। जो सरकार कभी नागरिक और उसकी जरूरत के बीच में रुकावट बन जाती थी, वह अब किनारे हटकर उसका आगे बढ़ने का मार्ग बना रही है। भारत शब्द के पीछे यही मूल भावना है। मैं जिस पद पर हूँ, वहाँ से इस बदलाव के बारे में बात कर सकता हूँ। साल 2014 में, हमारे पेट्रोल में इथेनॉल संमिश्रण का स्तर 1.53 प्रतिशत था। इस वर्ष हम बीस प्रतिशत के स्तर पर पहुँच चुके हैं—एक ऐसा लक्ष्य जो कभी

2030 के लिए तय किया गया था और जिसे हमने आधा दशक पहले ही हासिल कर लिया है। वह पैसा जो कभी कचे तेल की खरीद के लिए देश से बाहर चला जाता था, वह अब हमारे किसानों तक पहुँच रहा है, जो हमें अन्न देने वाले अन्नदाता के साथ-साथ अब ऊर्जा देने वाले ऊर्जादाता भी बन गए हैं। इन्हीं वर्षों में, उज्ज्वला योजना ने पहली बार दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुँचाई और इसकी सॉफ़्टडी बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभार्थी के खते में भेजी गई। यह अंत्योदय का ही एक रूप है, जो अब लीटर और सिलेंडर के माध्यम से साकार हो रहा है। अब योजनाएँ समाज के आखिरी पायदान पर पहुँच चुकी हैं, जिनके पास कभी नहीं करतीं, बल्कि उन्हीं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। यही लेखा-जोखा ईट और स्टील के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। आवास योजना के तहत उन परिवारों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं, जिनके पास कभी कोई घर नहीं था। 2014 में केवल पांच शहरों में मेट्रो चलती थी, आज बीस से अधिक शहरों में दौड़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, और उड़ान योजना ने उन छोटे शहरों के लोगों के लिए भी हवाई यात्रा सुगमिन बना दी है, जहाँ के लोग पहले सिर्फ़ आसमान से गुज़रते हुए हवाई जहाजों को देखा करते थे।

रेलवे का लगभग पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है और अब वहाँ देश में ही निर्मित सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। ये सब कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। हर बदलाव का मतलब है—लंबी लाइनें खत्म हुईं, सफ़र में अब पूरा दिन बर्बाद नहीं होता और रेल के टिकटों के माध्यम से साकार हो रहा है। अब योजनाएँ समाज के आखिरी पायदान पर पहुँच चुकी हैं, जिनके पास कभी नहीं करतीं, बल्कि उन्हीं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। यही लेखा-जोखा ईट और स्टील के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। आवास योजना के तहत उन परिवारों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं, जिनके पास कभी कोई घर नहीं था। 2014 में केवल पांच शहरों में मेट्रो चलती थी, आज बीस से अधिक शहरों में दौड़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, और उड़ान योजना ने उन छोटे शहरों के लोगों के लिए भी हवाई यात्रा सुगमिन बना दी है, जहाँ के लोग पहले सिर्फ़ आसमान से गुज़रते हुए हवाई जहाजों को देखा करते थे।

बाकी चीज़ों के साथ-साथ वित्तीय ढांचा भी बदला। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने, अपनी शुरुआती तमाम दिक्कतों के बावजूद, देश को एक साझा राष्ट्रीय बाजार दिया—एक ऐसा बाजार जिसे बनाने के प्रयास में पिछले दो दशकों की हर वह सरकार नाकाम रही थी जिसने इसके लिए कोशिश की थी। केंद्र और राय अब ईजू ऑफ़ ड्रूंग्स बिजनेस (व्यापार करने की सुगमता) और वितरण (सेवाओं को जनता तक पहुँचाने) की गुणवत्ता पर एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, यह आवंटन को लेकर भी उन्हें वाले पुराने झगडे से कहीं अधिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसी भरोसे ने विदेशों में भारत की छवि को बदला है और देश का प्रतिनिधित्व करने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं यह बात कह सकता हूँ। पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति एक ऐसे गरीब और नए देश के लिए समझदारी भरा कदम था जो किसी एक पक्ष को चुनने का जोखिम नहीं उठा सकता था।

टीएमसी का वजूद भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है?

सखेंद्र प्रताप सिंह

यह प्रश्न पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है। आखिर कोई दल अपने प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को क्यों बनाए रखना चाहेगा ? लेकिन राजनीति में प्रतिद्वंद्वी का पूरी तरह समाप्त हो जाना हमेशा लाभकारी नहीं होता। कई बार एक मजबूत और स्पष्ट विरोधी का बने रहना राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी साबित होता है।

पश्चिम बंगाल में पिछले एक दशक के दौरान भाजपा और टीएमसी के बीच स्पष्ट राजनीतिक ध्रुवीकरण विकसित हुआ है। भाजपा ने राज्य में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक वृद्धि इसी द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर दर्ज की। सत्ता-विरोधी भावना, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा तथा पहचान आधारित राजनीति जैसे मुद्दों ने भाजपा को मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यदि भविष्य में टीएमसी का संगठनात्मक या राजनीतिक क्षरण होता है, तो यह आवश्यक नहीं कि उसका पूरा लाभ स्वतः भाजपा को ही मिले। टीएमसी के सामाजिक आधार, कार्यकर्ता नेटवर्क और मतदाता समर्थन का एक हिस्सा विशेषकर वामपंथी दलों की ओर भी स्थानांतरित हो सकता है।

ऐसी स्थिति में भाजपा को एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के बजाय कई प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के लिए वह परिदृश्य अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जा सकता है जिसमें मुकाबला मुख्यतः भाजपा बनाम टीएमसी के रूप में प्रस्तुत हो।

इससे चुनावी विमर्श अधिक स्पष्ट रहता है और मतदाताओं के सामने विकल्प भी अपेक्षाकृत सरल रूप में दिखाई देते हैं। बंगाल में हाल के वर्षों में द्विध्रुवीय राजनीति ने भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि यदि टीएमसी के भीतर किसी वैकल्पिक नेतृत्व या गुट को कानूनी और संस्थागत मान्यता मिलती है, तो इससे पार्टी का एक स्वरूप राजनीतिक रूप से जीवित रह सकता है।

ऐसी स्थिति में बंगाल को राजनीति पूरी तरह पुनर्संरचित होने के बजाय एक नए संतुलन की ओर बढ़ सकती है। भाजपा के लिए यह स्थिति इसलिए भी सुविधाजनक हो सकती है क्योंकि इससे विपक्षी राजनीति का केंद्र पूरी तरह वामपंथी हाथों में नहीं जाएगा।

एक अन्य तर्क यह है कि टीएमसी के कमजोर होने से राज्य में वामपंथी राजनीति के पुनरुत्थान की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पिछले डेढ़ दशक में टीएमसी ने सामाजिक कल्याण, जनआंदोलन और राजनीतिक लामबंदी जैसे अनेक ऐसे राजनीतिक आजारों का इस्तेमाल किया जिन्हें कभी वामपंथी राजनीति की पहचान माना जाता था।

परिणामस्वरूप वामपंथी दलों के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को पुनर्गठित करना कठिन हुआ। भाजपा और वामपंथी दलों के बीच वैचारिक संघर्ष का इतिहास भी लंबा रहा है।

इसलिए भाजपा के कुछ रणनीतिकारों की दृष्टि में टीएमसी की उपस्थिति वामपंथी पुनरुत्थान के विरुद्ध एक अवरोधक की भूमिका निभा सकती है। हालांकि यह आकलन राजनीतिक परिस्थितियों और शक्ति संतुलन के अनुसार बदल भी सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी टीएमसी का अस्तित्व भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सकता है। टीएमसी भाजपा की प्रमुख आलोचक रही है, लेकिन वह कांग्रेस-नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधनों के भीतर भी अक्सर स्वतंत्र राजनीतिक रुख अपनाती रही है।

इससे विपक्षी एकता के प्रयासों में समय-समय पर अंतर्विरोध उभरते रहे हैं।

इससे विपक्षी एकता के प्रयासों में समय-समय पर अंतर्विरोध उभरते रहे हैं।

जब सत्ता की मलाई छीन गई, यदि अभिषेक बनर्जी की अगुआई में पार्टी जीत गई होती और इनका लूट खसोट का धंधा चलता रहता तो इनकी आज जागी हुई आत्मा सोई पड़ी रहती।

आज जो सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं उनमें से दस पहली बार चुनकर आए हैं। ये तुणमूल नेताओं की वो पीढ़ी है जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नया चेहरा बनाकर आगे बढ़ाया था। अब यही लोग अपना भविष्य सुधारने के लिए ममता दीदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं बंगाल में सत्ता में आई पार्टियाँ कम से कम डेढ़-दो दशक सत्ता में रहती हैं, इस तरह आने वाले 15–20



वर्षों तक इनका कोई भविष्य नहीं होगा।

तुणमूल नेताओं के प्रति जनता के गुस्से का आलम ये है कि चुनाव में पार्टी को धूल चटाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा है। आए दिन तुणमूल नेताओं की सड़कों पिटाई की जा रही है। तुणमूल नेता जहां भी जाते हैं जनता उन्हें चोर-चोर कहकर पुकारती है और उन पर टमाटर-अंडे फेंकती है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओ तक पर अंडे टमाटर फेंके जा चुके हैं और पिटाई हो चुकी है। यह भी संभव कि बंगाल की जनता में व्याप्त इस भयंकर आक्रोश से बचने के लिए भी तुणमूल नेता बगावती हो रहे हों।

तुणमूल के जिला स्तरीय नामचीन नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती, बिधान नगर के मेयर कृष्णा चक्रवर्ती और कटवा म्युनिसिपलिटी चेयरमैन कमलकांत चक्रवर्ती ने सौ से अधिक पार्षदों सहित इस्तीफा दे दिया है। राज्यभर से तुणमूल से लगातार इस्तीफों व बगावत के समाचार आ रहे हैं। हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर व दक्षिण –24 परगना जैसे गढ़ों में प्रतिदिन पंचायत सदस्यों के पाला बदलने की खबरें आ रही हैं। टीएमसी में बगावत व इस्तीफों के बाद कोलकाता नगर निगम ही भंग कर दिया गया है।

बंगाल में यह भी दावा किया जा रहा है कि इनमें से बहुत से लोग जेल जाने से बचने के लिए यह तरीका अपना रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल का कुख्यात चेहरा और चुनावों के दौरान अपने आप को पुष्पा कहने वाला फाल्टा विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार जहाँगीर खां के जेल जाने से अफरा तफरी का माहौल है। तुणमूल नेताओं के पाप जैसे उतरा रहे हैं। बंगाल पुलिस को संदेशखाली के तालाब से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, एक खेत से करोड़ों का कैश और हथियार मिले हैं। बमों व अन्य हथियारों की फैक्ट्रियां मिल रही हैं। हजारों की संख्या में सफेद साड़ियाँ मिली हैं जो तुणमूल ने चार मई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की विधवाओं को देने के लिए रखी थीं यदि गलती से भी तुणमूल जीत जाती तो यही लोग जो आज इस्तीफा देकर भाग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के नर संघर का नेतृत्व करते।

अपराधों की जो फेहरिस्त है उसे देखकर लगता है कि ममता दीदी और उनके चाटुकारों का शेष जीवन अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने या फिर जेल में ही बीतने वाला है। एक समय वाराणसी लोकसभा से पीएम नरेंद्र मोदी को हराने और दिल्ली आकर इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली ममता दीदी के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा कर रखना भी मुश्किल हो चुका है।

नया भारत अवसरों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का है

देवेश कुमार

भारत के लिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल का पिछला 12 वर्ष केवल शासन परिवर्तन का ही नहीं, युग परिवर्तन का कालखंड बन गया है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ हुई यात्रा ने भारत को केवल आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं किया, बल्कि उसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आध्यात्मिक मूल्यों और सभ्यतागत चेतना से पुनः जोड़ने का कार्य भी किया। इन वर्षों में भारत ने विकास और विरासत, आधुनिकता और परंपरा, विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शासन की बागडोर संभालते समय एक ऐसे भारत की कल्पना प्रस्तुत की थी, जो आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अपनी जड़-जमीन की पहचान को लेकर गौरवान्वित हो। यह दृष्टि केवल नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से एक राष्ट्रीय अभियान का रूप लेती चली गयी। परिणामस्वरूप, आज का भारत अवसरों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का नया भारत बनकर विश्व मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। ह्यमोदी के नेतृत्व में विकास को केवल आर्थिक सूचकांकों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि विकास का मतलब आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना माना गया। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और वरिष्ठ वर्ग को केंद्र में रखकर अनेक योजनाएं प्रारंभ की गयीं। जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलायी, आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया और प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों को सम्मानजनक जीवन का आधार दिया। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत अभियान ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया। जल-जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। आधुनिक राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे, रेलवे का तीव्र विस्तार, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल

सेवाएं, नये हवाई अड्डे और डिजिटल कनेक्टिविटी ने देश के विकास को नयी गति दी। जो क्षेत्र कभी विकास की मुख्यधारा से दूर माने जाते थे, वे आज राष्ट्रीय प्रगति के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान से शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। भारत आज विश्व का अग्रणी डिजिटल भुगतान वाला राष्ट्र बन चुका है। तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और योजनाओं के लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है।

यदि इन 12 वर्षों की उपलब्धियों को एक वाक्य में व्यक्त करना हो, तो कहा जा सकता है कि भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाये हैं। ‘आत्मनिर्भर भारत’ का मंत्र केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ और नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों ने युवाओं को नये अवसर प्रदान किये हैं। आज भारत वैश्विक विनिर्माण, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा भी इन 12 वर्षों की उल्लेखनीय उपलब्धि है। जी-20 की सफल अध्यक्षता, जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्वकारी भूमिका, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मुखर करना तथा विश्व के प्रमुख देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना भारत की बढ़ती शक्ति के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विशेषता केवल विकास नहीं, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण भी है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक विकास और विरासत को परस्पर विरोधी माना जाता रहा, किंतु बीते 12 वर्षों में यह स्थापित हुआ कि अपनी जड़ों से जुड़कर भी आधुनिकता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। ‘काशी विश्वनाथ धाम’ का पुनर्विस्तार इस सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। सदियों पुरानी आस्था को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए काशी को नयी गरिमा प्रदान की गयी। उज्जैन में ‘महाकाल लोक’, ‘केदारनाथ धाम’ का पुनर्निर्माण, ‘सोमनाथ’ और अन्य तीर्थ स्थलों का विकास भारतीय सांस्कृतिक चेतना को नये आयाम प्रदान करता है।

आज के समय में स्मार्ट नहीं

हार्ड वर्किंग है जरूरी

जब भी लम्बे काम की लिस्ट करने की जरूरत पड़ जाए तो छोटे ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए। इससे फोकस बढ़ता है और थके हुए दिमाग को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना कि आज रिलैक्स करके काम कल करेंगे ये गलत लालच है। लम्बे ब्रेक्स आलस पैदा करते हैं। अगर सी तरह के ब्रेक्स लेंगे तो आपके काम पर असर जरूर पड़ेगा। काम करते रहने से ही सफलता मिलती है।

खराब क्वालिटी का काम मिल सकता है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की आप रोज क्या काम करते हैं। अगर आप काम को पूरा समय नहीं देते हैं तो नतीजे बिगड़ सकते हैं। जो लोग मेहनत करने से बचते हैं और स्मार्ट वर्किंग तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके काम की क्वालिटी खराब होने की सम्भावना ज्यादा होती है। स्मार्ट वर्किंग करने वाले अक्सर अपने वर्कप्लेस पर सालों तक एक ही पोजिशन पर बने रह जाते हैं। जैसे अगर आप एक दिन में पांच प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वे अच्छी क्वालिटी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए चाहे एक दिन में कम काम करें लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए।



मेहनत हमेशा रंग लाती है

बात उस बॉस की नहीं है जो आपको मेहनत को देखते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। बात मेहनत के उस तजुर्बे की है जो आपको ऑफिस में सबके बीच मिलता है। हो सकता है आपको प्रोमोशन नहीं मिले लेकिन एक्सपीरिएंस जरूर मिलेगा और धीरे धीरे आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसी तरह तजुर्बे लेकर एक दिन आप अपना ड्रीम जॉब भी हासिल करेंगे। अगली बार आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे तो तुरंत उसे रिजेक्ट नहीं कर दें। कुछ मिनट रुकें और सोचें की क्या ये एक्स्ट्रा काम किसी भी तरह से भविष्य में मेरा भला कर सकता है? अगर जवाब हां में मिले तो उसे कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे काम भी करें जो आपकी जवाबदारी या जिम्मेदारी में नहीं आते हैं। आप कभी इन्हे रिप्ट नहीं करेंगे। हर हालत में मेहनत का फल तो मिलता ही है। ऐसे पर फोकस करना बंद कर दें और तजुर्बा लेने की जिद पकड़ें।

कैरियर

इन संकेतों से जानें

रिश्ते

कैसे बड़े रिश्तों की उम्र

हर कोई अपने जीवनसाथी की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाता है। एक साथ खुशनुमा जीवन बिताने वाली जोड़ियां बहुत समझदार, बहुत पैसे वाली या मनोविज्ञान की गहरी समझ रखने वाली हो ऐसा नहीं है। अगर लोग अपने रिश्ते में कुछ चीजों को जोड़ते रहते हैं तो रिश्ते लंबे समय तक टिके रहते हैं।

प्यार जताने का तरीका

अपने रिश्ते में समय-समय पर प्यार जताना जरूरी होता है ताकि आपके साथी को यह लगता रहे कि आपके लिए इस जुंवा की अहमियत है। जीवनसाथी के लिए फूल खरीदना या फिर उसकी पसंद की चीजें करने का अपना महत्व है। यह बहुत छोटी-सी बात लग सकती है लेकिन किसी भी रिश्ते में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी भी रिश्ते में जब एक व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है तो यहीं से दरार पड़ना शुरू होती है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो रिश्ता ताउम्र बना रहता है। ऐसे जीवनसाथी कभी भी संवाद की कमी, पैसों की दिक्कतों या फिर रिश्तेदारों के कारण रिश्ते को खत्म नहीं करते हैं।

गलतियों को मान लेना

हर रिश्ते में लड़ाइयां और गलतफहमियों के लिए गुंजाइश होती है। लेकिन जब दोनों ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की समझबूझ रखते हैं तो रिश्ता हरा-भरा रहता है। अपनी गलती स्वीकारना अपने कद को छोटा करना नहीं है बल्कि यह तो बड़प्पन को बताता है। जब आप अपने अहम को छोड़कर अपने साथी को मनाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में एकदूसरे लिए पर्याप्त प्रेम है। अपने साथी की परिस्थिति को समझना भी बहुत ही मायने रखता है क्योंकि उससे भी दूरियां खत्म हो जाती हैं और शिकवों के लिए जगह नहीं रहती।

बातचीत का लहजा

आप क्या कहते हैं यह उतना मायने नहीं रखता है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप किस तरह से कहते हैं। बातचीत करते हुए अगर आप किसी बात को बहुत गुस्से में कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया वैसी ही होगी जबकि अगर आप उसे समझाने के अंदाज में कहते हैं तो उसका असर दूसरी तरह होता है। किसी भी बहस में आपको अपने साथी के प्रति बहुत

ही नपे-तुले शब्दों का उपयोग करना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर आप अपने साथी के साथ किस तरह बात करते हैं उसी से आप दोनों का जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। याद रखिए आपको टोन किसी भी बात को कहते हुए मायने रखती है।

किस तरह ध्यान देते हैं

जब भी आपका जीवनसाथी आपको मैसेज करता है तो आप किस तरह और कितनी देर में उसका जवाब देते हैं इससे भी पता चलता है कि आपका रिश्ता किस दौर से गुजर रहा है। जो अपने जीवनसाथी के फोन या संदेश को महत्व नहीं देते हैं वे अपने रिश्ते को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। जिस रिश्ते में दोनों ही साथी एकदूसरे के साथ चीजें शेयर करते रहते हैं या फिर एकदूसरे को जिंदगी के अनुभवों के बारे में बताते रहते हैं वह लंबे समय तक टिका रहता है। एकदूसरे के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए शेयरिंग बहुत ही अहम है।

एकदूसरे को स्वीकार करना

किसी रिश्ते की शुरुआत में दो व्यक्तियों में बहुत ज्यादा प्रेम होता है और तब सारा ध्यान खूबियों पर ही होता है लेकिन समय के साथ एकदूसरे की कमियां भी सामने आती हैं। लेकिन इन कमियों को नजरअंदाज करके अगर आप खूबियों पर ही ध्यान लगाएं तो रिश्ता कायम रहता है। जब आप किसी भी कमजोरी या कमी को ज्यादा बड़ा करके देखने लगते हैं तो चीजें खराब मोड़ लेने लगती हैं। किसी भी खुशहाल रिश्ते में एकदूसरे से प्रेम के अलावा किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है परफेक्शन तो आपको तलाशना पड़ता है।

खाली समय कैसे गुजारते हैं

अगर आप दोनों अपना खाली वक्त एकदूसरे के साथ गुजारना पसंद करते हैं तो समझिए कि आपका रिश्ते बिल्कुल सुरक्षित अगर आप दोनों अपना खाली वक्त एकदूसरे के साथ गुजारना पसंद करते हैं तो समझिए कि आपका रिश्ते बिल्कुल सुरक्षित अगर आप दोनों अपना खाली वक्त एकदूसरे के साथ गुजारना पसंद करते हैं तो समझिए कि आपका रिश्ते बिल्कुल सुरक्षित अगर आप दोनों अपना खाली वक्त एकदूसरे के साथ गुजारना पसंद करते हैं तो समझिए कि आपका रिश्ते बिल्कुल सुरक्षित

दायरे में हैं। अक्सर लोग अपने खाली वक्त में अकेले कहीं जाना पसंद करते हैं या उन चीजों को करने के बारे में सोचते हैं जो लंबे समय से अटक पड़ी है। तब जीवनसाथी को मिलने वाला वक्त और भी कम हो जाता है। ऐसे में आपसी उलझनों को सुलझाने का समय ही नहीं मिलता है। संवाद से सारी चीजों का हल निकाला जा सकता है मगर तब क्या होगा जब इस संवाद के लिए समय ही न हो। साथ बिताया जाने वाले समय को ज्यादा न हो लेकिन जितना हो वह शानदार ढंग से बीते तो रिश्ता बेहतर होता है।

बेडरूम में भूलकर

भी न रखें फूल



फेंगशुई में घर को शरीर के समान माना जाता है। फेंगशुई में हर छोटी-बड़ी चीज का महत्व है। अगर घर में गलत स्थान पर कोई चीज रखी है तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। फूलों से घर को सजाने में भी हमें फेंगशुई के सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए।

घर में अगर फूलों को सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। अपने घर में फूलों को हमेशा लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में लगाना चाहिए। बेडरूम में फूलों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों में बैचैनी हो सकती है।

फेंगशुई के अनुसार बांस के पौधे सुख-समृद्धि के प्रतीक हैं। इनसे परिवार के सदस्यों को पूर्ण आयु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर की बैठक में बांस का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के छोटे से पात्र में नमक भरकर रख दें। हर दिन इस नमक को बदलते रहें।

घर में खुशहाली के लिए तीन हरे पौधे मिट्टी के बर्तनों में घर के अंदर पूर्व दिशा में रखें। ये पौधे बोनसाई या कैक्टस के न हों। घर, कार्यालय, शोरूम के पूर्वी हिस्से में लकड़ी का फर्नीचर रखने से लाभ मिलता है। अपने लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में फेश फूलों को लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

घर में रखे फूल अगर सूखने या मुरझाने लगें तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सूखे फूलों को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। फेंगशुई में माना जाता है कि सूखे हुए फूलों से नकारात्मक ऊर्जा आती है। आप अपने घर में प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूल भी लगा सकते हैं।

वास्तु

जानें इंडिया के बेस्ट मानसून स्पोर्ट्स के बारे में....

अगर आप इस मॉनसून में अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं और आपको समझ न आ रहा है कि कहां जाएं तो हम आपको इसमें मदद कर देते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसी हसीन वादियों के बारे में जहां जाकर आप इस भागती दौड़ती जिंदगी के तनाव से आजाद होकर अपने पार्टनर के साथ हसीन लम्हों का मजा उठा पाएंगे। इन जगहों पर न सिर्फ आपको खूबसूरत मौसम मिलेगा बल्कि,यहां टंडी-टंडी फुहारों में भीगने का मजा ही कुछ और होगा। ये हैं इंडिया के बेस्ट मानसून स्पॉट जहां आप जरूर जाना चाहेंगे। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का स्वर्ग हैं। यहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यह शहर चाय बागान के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। मानसून के मौसम में दार्जिलिंग की सैर एक अनोखा और यादगार पल होगा। क्योंकि चारों और फैले चाय के बागान और दार्जिलिंग की हसीन वादियां आपका मन मोह लेंगे। गोवा यह बीच अपने भव्य प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को सम्मोहित करता है। यहां कुदरत का नजारा देखते ही बनता है। समुद्र के किनारे झुके हुए खजूर के पेड़ और सफेद चमकीले रेत इस बीच की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस बीच को पहले हिप्पियों का बीच कहा जाता था। अगर आप मोलभाव में अच्छे हैं, तो आपको मोलभाव करके खरीदारी में मजा आता है तो यहां लगाने वाला बाजार भी आपके लिए एक आकर्षण है। इस बीच पर चांदनी रातों में हिप्पियों की पार्टियां होती हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। शिलांग, मेघालय



मेघालय की राजधानी शिलांग एक बेहद खूबसूरत आकर्षक स्थल है। पहाड़ियों पर बसा यह छोटा सा शहर हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहां पर मानसून का अपना अलग ही मजा है। वैसे तो यहां पूरे साल मौसम सुहावना रहता है लेकिन मानसून में यहां के मौसम में चार चांद लग जाते हैं। कुर्ग, कर्नाटक पश्चिमी घाटों में फैला हुआ कुर्ग की मिस्ट्री घाटी में खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां कॉफी, चाय और मसालों के पेड़ हैं। कुर्ग को इसकी खूबसूरती और यहां के खुशनुमे मौसम के चलते भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहां कॉफी और मसालों की खेती होती है। कुर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र में मंडालपत्ती, तिब्बती मठ, कावेरी नदी, इरूपू फॉल, इगुथापा मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, मरकारा डाउन गोल्फ क्लब, ब्रह्मागिरी पहाड़ी और नाल्कनाद महल है। मुन्नार, केरल मुन्नार में विशाल

पर्यटन

चाय बागान और घुमावदार गलियों की वजह से मुन्नार भारत के फेमस हिल स्टेशन में से एक है। यहां भारतीय मसालों की खुशबू आती है क्योंकि यहां मसालों की खेती होती है। यहां पर्यटकों के बीच हाउसबोटिंग काफी पॉपुलर है। मुन्नार के प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र में चाय के बगीचे, वॉन्डला अम्यूसमेंट पार्क, कोची फोर्ट, गणपति मंदिर और हाउसबोट है।



कभी भी हो सकती है

नई शुरुआत

जर्मन कवि बर्तोल्त ब्रेख्त की पंक्तियां हैं-
जो हो चुका सो हो चुका, हर चीज बदलती है,
अपनी हर आखिरी सांस के साथ,
तुम कर सकते हो ताजा शुरुआत...।

किसी भी काम की शुरुआत के लिए जरूरी नहीं कि कोई मुहूर्त ही हो। जब आपकी इच्छा हो, मन में जुनून हो तभी एक नई शुरुआत की जा सकती है। यदि पूर्व में असफलता भी मिली हो तो उससे घबराना कैसा। आगे तो बढ़ना ही है जिसके लिए पहला कदम भी बढ़ाना ही होगा। नई शुरुआत तभी संभव है जब बुरी

व्यक्तित्व विकास

विश्वविद्यालय में यादों को भुलाकर नए दृष्टिकोण के साथ शुभ कदम बढ़ाएं। प्रयास करें, हारें, फिर प्रयास करें, यही तो जीवन है। अमेरिकी टीवी होस्ट ओप्रा विनफ्रे ने एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसा काम करें जिसे असंभव समझते हों। विफल हों, फिर प्रयास करें। केवल वे लोग ही नहीं गिरते, जो कभी चुनौतीपूर्ण काम नहीं करते। हार भी आपकी है, इसलिए अपनी हार का भी आनंद लें। हम सभी कभी न कभी असुरक्षित महसूस करते हैं। संबंध, करियर, सेहत...ऐसे कई पहलू हैं, जिनमें विफलता की चिंता होती है। इससे बचाव के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए यदि इन चार बातों पर ध्यान दें तो जिंदगी आसान होगी।

1. दो नावों में न रहें सवार

एक ही बार में दो अलग-अलग दिशाओं में चलना मुमकिन नहीं तो ऊर्जा व्यर्थ क्यों करें? सिर्फ थोड़ा-सा पाने के लिए अगर रोज इच्छा के खिलाफ काम करना पड़े तो बेहतर है वह करें जो करना चाहते हैं। लेकिन पहले यह जान लें कि करना क्या चाहते हैं। दुविधा में रहने और आगे कदम न बढ़ाने से विफलता ही मिलेगी, इसलिए दृढ़-इच्छा से आगे बढ़ें। एक नई शुरुआत के लिए कोई समय नहीं होता, वह तो कभी भी शुरू की जा सकती है।

2. समय है 'हां' कहने का

सही दिशा में कदम बढ़ाने के बाद

डर की कोई वजह नहीं रहना चाहिए। जीवन को पूरे जज्बे के साथ जीने की चाह रखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। अतीत से सबक लेकर मौजूदा स्थिति पर नियंत्रण रखें। फैसलों पर अडिग रहें। नए अवसरों को स्वीकार करें तभी तो किसी काम की शुरुआत होगी।

3. नजरिया बदलें

सोच बदले बिना नतीजे नहीं बदले जा सकते। सोच एक-सी रहेगी तो नतीजे भी एक जैसे ही मिलेंगे। इसलिए नए विचारों को दिल में जगह दें। दृष्टिकोण बदलने को तैयार रहें। हर चीज बदलती है, इसी का नाम जिंदगी है।

4. डर कैसा हार से

समाजशास्त्र विभाग की प्रो. अनीता मिनाचा कहती हैं जब हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते तो अतीत अधिक खुशगवार लगता है। अतीत कितना भी अच्छा हो, उसे लौटा तो नहीं सकते। इसलिए सचाई स्वीकारें। हर चुनौती का सामना करें और एक नई शुरुआत में जुट जाएं।

सफलता का स्वाद

कभी-कभी कोई उदाहरण हमें वह सबक भी सिखा जाता है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वे जीवन के 51वें पड़ाव पर राष्ट्रपति चुने गए। इस बड़ी सफलता का अध्ययन दरअसल अनेक विफलताओं की बुनियाद पर लिखा गया। उम्र के 22वें वर्ष में बिजनेस में उन्हें नुकसान हुआ, 23वें वर्ष में राजनीति में कदम रखा, मगर हार गए, 24वें वर्ष में फिर व्यापार में नुकसान हुआ, 26वें वर्ष में उनकी मंगेतर का निधन हो गया, फिर खुद बीमार हो गए। एक बार फिर उन्होंने स्पीकर का चुनाव लड़ा। यह उम्र का 29वां पड़ाव था लेकिन यहां भी उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। 31 वें वर्ष में फिर उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया लेकिन फिर चुनाव हारे। 46 की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ा और हारे। विफलताओं से उनका बेहद करीबी रिश्ता रहा, लेकिन एक दिन यही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया।

सार-संक्षेप

जल्द भारत में मजबूत प्रधानमंत्री होगा जो हर अपमान का बदला लेगा

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक संदेश में दो टुक कहा कि जल्द भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा, जो अमेरिका से हर अपमान और हत्या का बदला लेगा । केजरीवाल ने एक्स पर ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि जिन भारतीयों की जान गई है, उसके लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा । आप एक कायर और बेरहम हत्यारे हैं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं । लेकिन जल्द ही, भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा । वह प्रधानमंत्री आपको आपके कुकर्मों की सजा जरूर देगा । उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, आज पूरे देश का खून खील रहा है ।

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया

नई दिल्ली । संघ सेवा लेका आयोग (यूपीएससी) ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए, जिसमें कुल 13,343 उम्मीदवार सफल हुए हैं । यह प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की गई थी । यूपीएससी द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा, 2026 के लिए अधिसूचित 1,016 रिक्तियों के मुकाबले कुल 13,343 उम्मीदवारों को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026 के लिए चयनित किया गया है । पिछले वर्ष (2025) की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए 1,087 रिक्तियों के मुकाबले 14,14,161 उम्मीदवारों को चयनित किया गया था । यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा(आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन करने के लिए हर वर्ष प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार/व्यवित्त परीक्षण समेत तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है ।

नीट पुनर्परीक्षा: गृह सचिव ने की राज्यों की तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सोमवार को नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की । विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में छात्रों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया गया । तीन मई को आयोजित मंडिकल प्रवेश परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था । पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है । गृह सचिव ने निदेश दिया कि सुरक्षा संबंधी सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और परीक्षा का आयोजन न्यूट्रलित तरीके से सुनिश्चित किया जाए । बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और डाक विभाग के सचिव, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीसीएस और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक तथा रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए । बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया ।

वैष्णो देवी यात्रा : इस बार टूट जाएगा पिछला रिकॉर्ड

जम्मू । वैष्णो देवी के तीर्थस्थान पर इस बार जिस प्रकार श्रद्धालुओं की संख्या हिलोरे मार रही है उससे यह उम्मीद बंधने लगी है कि आने वाली की संख्या इस बार पिछले सारे रिकार्ड तोड़ देगी। उम्मीद संख्या के एक करोड़ के आंकड़े को पार करने की है।

वैसे भी जून में अब तक 5.55 लाख से अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं, जबकि इस वर्ष जनवरी से अब तक 46 लाख से अधिक श्रद्धालु मां के दरबार में नतमस्तक हो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह इस वर्ष यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है, उसे देखते हुए वर्ष 2026 में यात्रा का आंकड़ा एक करोड़ का रिकार्ड पार कर सकता है।

रिकार्ड के तौर पर 13 जून को करीब 48,500 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी। यात्रा पंजीकरण केंद्रों से लेकर यात्रा मार्ग, सुरक्षा जांच केंद्रों और भवन परिसर तक हर तरफ श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वर्ष 2026 में सबसे अधिक 10.92 लाख श्रद्धालु आए हैं जबकि पिछले

तृणमूल कांग्रेस के बागियों के विलय की खबर पर एनसीपीआई नेतृत्व हैरान, उठाए सवाल

राष्ट्रीय सचिव ने कहा- पार्टी नेतृत्व में नहीं हुई चर्चा, एकतरफा नहीं हो सकता ऐसा कोई निर्णय

कोलकाता, एजेंसी

त्रिपुरा में ‘अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, दलबदलू नेताओं को नकारे’ नारे के साथ 2023 के चुनाव में उतरी नेशनलिस्ट सिटीजनस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की ओर से अपनी पार्टी अपने विलय की घोषणा किए जाने को लेकर हैरान है। एनसीपीआई के राष्ट्रीय सचिव शांतनु डे ने इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व में इस मुद्दे पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है और ऐसा कोई निर्णय एकतरफा नहीं लिया जा सकता है। शांतनु डे के इस दावे के बाद बागी टीएमसी सांसदों का विलय अनिश्चितता में धिर गया है।

एनसीपीआई के राष्ट्रीय सचिव शांतनु डे ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने अन्य पदाधिकारियों ने विलय के किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले को संगठनात्मक मंजूरी नहीं मिली थी। उन्होंने बताया, पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी के भीतर विलय के बारे में कभी कोई बात नहीं की। ऐसे फैसले वह अकेले नहीं ले सकते। शांतनु के इस बयान से संगठन के भीतर तृणमूल के बागी सांसदों के

एनसीईआरटी डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर प्रकाशित करेगी

नई दिल्ली, एजेंसी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नौवीं कक्षा की नई पाठ्यपुस्तक में ‘डांसिंग गर्ल’ के नाम से प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो की कांस्य प्रतिमा के निर्वस्त्र धड़ को ढका दिखाए जाने को लेकर हुई आलोचना के बाद मूल प्रतिमा की तस्वीर प्रकाशित करने का फैसला लिया है। यह फैसला तब लिया गया है, जब स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक कलाकृतियों में से एक डांसिंग गर्ल के चित्रण को लेकर बहस छिड़ गई। एनसीईआरटी कक्षा नौ की कला विषय की पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में डांसिंग गर्ल की संशोधित तस्वीर की जगह मूल तस्वीर प्रकाशित करने की एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने पुष्टि की। संशोधित तस्वीर मधुरिमा के पहले अध्याय “कला का इतिहास” में प्रकाशित की गई है। पुस्तक में प्रकाशित इस चित्र में प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मूल प्रतिमा की तस्वीरों की तुलना में बदला हुआ दिखाई दिया है। प्रतिमा के ऊपरी हिस्से पर छायांकन किया गया है, जिससे उसके शरीर के वे हिस्से उभरे दिखाई नहीं दे रहे जो मूल मूर्ति में नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत, एनसीईआरटी की कक्षा छह

वैष्णो देवी यात्रा : इस बार टूट जाएगा पिछला रिकॉर्ड

●**हिलोरे मार रही श्रद्धालुओं की संख्या, गर्मी की परवाह नहीं**

साल इसी महीने में आने वालों की संयंख पर आपश्चन सिंदूर का साया होने से संख्या 4.13 लाख ही थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सभी यात्रा पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं का जवद पंजीकरण कर उन्हें आरएफआईडी यात्रा कार्ड उपलब्ध कराया जा सके। इसके बावजूद पंजीकरण केंद्रों पर भारी भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और प्यास के बीच श्रद्धालु घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर रहे।

श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। पर बावजूद इसके बोर्ड की व्यवस्थाओं का दम फूल रहा है। दूसरी ओर प्रशासन, पुलिस तथा फेरिपुब के अधिकारी व जवान यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर तैनात रहकर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।



शांतनु डे, एनसीपीआई के राष्ट्रीय सचिव ।

संकरैल में एनसीपीआई कार्यालय पर अचानक भारी सुरक्षा

कोलकाता । नेशनलिस्ट सिटिजनस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) अचानक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के केंद्र में आ गई है । तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की इस पार्टी में विलय की घोषणा के बाद सोमवार को हावड़ा जिले के संकरैल के बानीपुर में पार्टी के पंजीकृत कार्यालय में पहली बार हलचल देखने को मिली। इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती देखी गई क्योंकि जगह के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। इस कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यवस्था बनाए रखने को कड़े इंतजामात करने पड़े । इस घटना ने पार्टी के कुछ संस्थापक सदस्यों को भी हैरान कर दिया है । एनसीपीआई के कई सदस्यों ने कहा कि उन्हें टीएमसी सांसदों के शामिल होने का पता सोशल मीडिया के जरिए चला । त्रिपुरा के एनसीपीआई नेता जहांगीर अली ने कहा कि ऐसी खबरें सुनी हैं कि 20 टीएमसी सांसद पार्टी में शामिल हो गए हैं लेकिन इसकी किसी ने कोई पुष्टि नहीं की है । उन्होंने अधिवक्ता शेउली कुंडु को पार्टी की अध्यक्ष भी बताया । एनसीपीआई का कार्यालय हाटगावा-बनौपुर में ‘जागो बिश्व’ नाम की दो मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में पंजीकृत है ।

विलय के मुद्दे पर वे मतभेद सामने आ गए हैं जो इस नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पैदा हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने इस गुमानाभ कक्षा को अचानक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। शांतनु ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से त्रिपुरा तक ही सीमित थीं और पश्चिम बंगाल

एनसीपीआई अध्यक्ष बताई जा रही शेवली कुंडु बोलीं- इस्तीफा दे चुकी हूं

शेवली कुंडु को एनसीपीआई का अध्यक्ष बताया जा रहा है । हालांकि, शेवली कुंडु ने दावा किया है कि वे पहले से ही एनडीए के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एनसीपीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है । शेवली ने कुछ न्यूज चैनलों को दिए साक्षात्कार में साफ किया वह अब पार्टी की अध्यक्ष नहीं हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था । उन्होंने बताया कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करती हैं और बढ़ती व्यावसायिक व्यस्तता के कारण संगठन को समय नहीं दे पा रही थीं, इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया । उधर, वर्तमान में एनसीपीआई के अधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार शेवली कुंडु इसके संस्थापक सदस्यों और कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज हैं, जबकि उनके पति उतिया कुंडु पार्टी के अध्यक्ष हैं ।

कानूनी राय ले सकते हैं बिरला

नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के एनसीपीआई में प्रस्तावित विलय के बाद उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग पर कानूनी राय ले सकते हैं । लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि बागी सांसदों की मांग पर कोई भी फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले किया जाएगा, जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है । बागी सांसदों की मांग पर निर्णय केंद्रीय विधि मंत्रालय की लिखित राय के आधार पर लिया जाएगा ।

मुलाकात के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को समर्थन देने के साथ ही एनसीपीआई में अपने विलय की घोषणा की थी । डे की टिप्पणियों से विलय की प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं और माना जा रहा है कि एनसीपीआई के रास्ते अलग राजनीतिक पहचान बनाने के

जयपुर में प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके से मारपीट

युवाओं की भीड़ के बीच घुसकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को मारे थप्पड़, दो आरोपी हिरासत में

जयपुर, एजेंसी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मारपीट करते हुए उन्हें कई थप्पड़ मारे। यह घटना उस समय हुई जब समर्थकों ने दीपके को कंधे पर उठा रखा था। पुलिस के अनुसार, दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। उधर, इस घटना के बाद दीपके ने प्रदर्शकारियों को संबोधित करते हुए लोगों से धर्म और जाति के आधार पर विभाजित नहीं होने की अपील की तथा विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ नारे लगाए।

इस घटना के बाद ‘एक्स’ पर जारी एक वीडियो संदेश में दीपके ने आरोप लगाया कि उन पर हमला उनके आंदोलन को बाधित करने की कोशिश का हिस्सा है लेकिन

आरटीआई अर्जी दायर करना नया धंधा बन गया

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से पूछा- सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले आप कौन

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने एक आरटीआई कार्यकर्ता समेत कुछ लोगों को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए सोमवार को टिप्पणी की कि सरकार से जानकारी मांगने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत अर्जी दायर करना एक नया धंधा बन गया है। आरटीआई कार्यकर्ता पर सड़क निर्माण के कार्य में सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने का आरोप है।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार के पृक्कोट्टर के रहने वाले सात वर्षीय अर्जवं ने कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जवाब



गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस से अपना पंजीकरण कराने की मांग की है, भागवत ने कहा कि संगठन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह खुले तौर पर अपनी गतिविधियां संचालित करता है। संघ प्रमुख ने कहा, बहुत-सी अपंजीकृत



अर्जों दायर करना नया धंधा बन गया है। केंद्र सरकार ने निधि जारी कर दी है तो वह सड़क निर्माण के कार्य की देखरेख भी करेगी। आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट! याचिका खारिज की जाती है। न्यायमूर्ति मेहता की राय से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति बिश्नोई ने कहा, इन सभी सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले आप कौन होते हैं, क्या आप कोई उच्च अधिकारी हैं। बहल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत

नगर निकायों के चुनाव में वोट डाल सकेंगे विधायक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के उन विधायकों को नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दे दी जो नगर पालिकाओं के पदेन सदस्य होते हैं। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चार जून के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें पदेन सदस्य विधायकों को वोट डालने से रोका गया था । सीजेआई सुर्यकांत और न्यायमूर्ति वी . मोहना की पीठ ने कहा, इस फैसले के मद्देनजर जहां भी अब तक नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं, वहां उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य जिनका क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र में आता है, वे नगरपालिका के पदाधिकारियों के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे।

देने से इन्कार कर दिया गया था ।

बहल के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। प्राथमिकी के अनुसार, बहल ने एक अन्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ मिट्टू के साथ मिलकर पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में जारी सड़क निर्माण कार्य में कथित तौर

तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ा पार्टी पर दावा करेंगे : अरूप

नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने दल को छोड़ा नहीं है, बल्कि इसके चुनाव चिह्न पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने इस कदम को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अवैध करार दिया है।

अरूप ने कहा, हम तृणमूल में ही हैं और पार्टी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पार्टी के चुनाव चिह्न के लिए लड़ेंगे। अरूप ने कहा, एक नया खेल शुरू हो गया है... खेला होवे । उन्होंने दावा किया कि इस कदम से पश्चिम बंगाल में विकास और रोजगार आएगा । पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी डरी हुई हैं, वह पार्टी की बैठक तक नहीं बुला सकतीं। वह चुनाव से पहले अपने चुनाव क्षेत्र में एक बैठक भी नहीं कर पाईं । उन्होंने कहा कि काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंद्योपाध्याय उनके गुट के नेता थे।

काकोली का बिरला को पत्र, कल्याण बनर्जी को निष्कासित करें, महिलाओं से करते हैं दुर्य्ववहार

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने सदन के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग की है । आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने बार-बार मौखिक दुर्य्ववहार किया, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की और संसद परिसर में अनुचित आचरण किया । कल्याण बनर्जी ने बागी सांसदों की आलोचना करते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें ।



जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की रैली में हजारों युवाओं की भीड़ जुटी ।

साथ मारपीट की । पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया ।

पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए आरोपियों में से एक राकेश गुर्जर ने स्वयं को राष्ट्रवादी बताते हुए आरोप लगाया कि दीपके की सोच जिहादी मानसिकता वाली है। वह

लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पेपर लोक का मुद्दा केवल एक बहाना है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि राजस्थान हाल के वर्षों में पेपर लोक की घटनाओं का प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र

और चार्टर्ड अकाउंटेंट देने वाला राज्य अब शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का सामना कर रहा है। रांका ने कहा कि प्रदर्शन में युवाओं की बड़ी भागीदारी उनकी बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

जंग खत्म, अब पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस ले सरकार

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बनने के बाद अब सरकार को पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए । पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री इसकी घोषणा फ्रांस से करेंगे या फिर देश लौटकर यह खुशखबरी देंगे ।

खेड़ा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, हमें बताया जा रहा था कि भारत की बेहाल अर्थव्यवस्था की वजह अमेरिका-ईरान की जंग है। हर महंगाई, हर गिरावट और हर परेशानी का दोष सरकार की नीतियों पर नहीं, पश्चिम एशिया के तनाव पर था। अब जब जंग खत्म हो गई है, तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए ।

कर्नाटक के गृहमंत्री ने की थी पंजीकरण कराने और संगठन की कानूनी और वित्तीय स्थिति स्पष्ट करनी की मांग

आरएसएस का पंजीकरण कराने की मांग राजनीति : मोहन भागवत

त्रिशूर, एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के पंजीकरण की मांग को खारिज करते हुए कहा कि संगठन के पास न तो कुछ छिपाने के जरिए है और न ही वह जनता की नज़रें से बचकर काम करता है। भागवत रविवार को केरल के त्रिशूर में आरएसएस के शताब्दी संपर्क कार्यक्रम के तहत एक सभा को संबोधित करने के बाद सवालों का जवाब दे रहे थे। यह पूछे जाने पर कि कर्नाटक के



चीजें संचालित हो रही हैं और हम कुछ छिपाते नहीं हैं। हम खुलेआम काम करते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम क्या करते हैं। उन्होंने आरएसएस के पंजीकरण की मांग को राजनीति करार देते हुए कहा कि संगठन के लिए ऐसी कोशिश कोई नई बात नहीं है। भागवत ने कहा, यह राजनीति है और हमें इसकी आदत हो गई है। संघ के अस्तित्व में आने के 10-15 साल बाद ही हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था। अगर ऐसा न हो तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि

देश-विदेश में 60,000 शाखाएं चलाने वाले संगठन को संविधान का पालन करना चाहिए : प्रियंक खरगे **बैंगलुरु** । कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए उसके प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है । इसमें संघ से आग्रह किया कि वह अपना पंजीकरण कराने के साथ अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करें और वित्तीयता के स्रोत, आय, खर्च और संपत्ति का खुलासा करें । उन्होंने कहा कि आरएसएस को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए । खरगे ने अपना पत्र एक्स पर साझा करते हुए कहा कि जिस संगठन की देश-विदेश में 60,000 से अधिक शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक होने का दावा है, उसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन भी करना चाहिए । खरगे ने कहा, संघ अपने 100वें साल में भारत को जो सबसे अच्छा सम्मान दे सकता है, वह यह होगा कि वह अपना पंजीकरण करए, अपनी गतिविधियों और आर्थिक लेनदेन की जानकारी दे, सभी लोग टैक्स चुकाए और भारतीय कानून के दायरे में रहकर एक पारदर्शी और जवाबदेह संगठन के तौर पर काम करें ।

12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अनुज शर्मा और पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला

डबल इंजन सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल एवं गौरवशाली 12वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नीलजा और ग्राम पंचायत सारागांव में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के साथ छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला ने ग्राम पंचायत नीलजा में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात कर श्रीफल ,पुष्पगुच्छ और शाल देकर आत्मीय सम्मान किए और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे मे जानकारी दिए। ग्राम पंचायत नीलजा में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान ,गांव के समाज के प्रमुखों का सम्मान किए।

तत्पश्चात ग्राम पंचायत नीलजा में भाजपा कार्यकर्ता के घर दोपहर भोजन करने के बाद ग्राम पंचायत सारागांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं,विभिन्न समाज के प्रमुख का श्रीफल,शाल, पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय सम्मान कर मुलाकात किए। तथा उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारो के साथ अपने उद्बोधन में कहा कि पहले कांग्रेस के



सरकार में कमीशनखोरी था ,जनता तक पैसा नहीं पहुंच पाता था,लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने लाल किले से जो वादा किया था सभी को पूरा कर रहे है। मोदी ने कहा था,न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबसे पहले

उन्होंने सभी का जनधन खाता खुलवाया, हर वर्ग के गरीबों को पक्का मकान, इलाज के लिए आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपये तक इलाज, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि, सुकन्या योजना, महतारी वंदना योजना, सभी

योजना हर वर्ग के गरीबों को लाभ मिल रहा है। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के सरकार ,और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ सभी वर्गों का चिंता करते हुए विकास कर रहा है।

जनसर्क कार्यक्रम में डॉ लखन धीवर उपाध्यक्ष मछवारा कल्याण बोर्ड , दिनेश खूटे उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धरसीवा, अशोक सिन्हा प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग, सविता चंद्राकर सभापति जिला पंचायत रायपुर, अरविंद ठाकुर भाजपा कोषाध्यक्ष, रोबिन साहू पूर्व मंडल अध्यक्ष,ग्राम पंचायत नीलजा सरपंच श्रीमती उमा देवांगन, सारागांव सरपंच धनाराम धीवर, उपसरपंच राजेंद्र यदु, राजेंद्र विश्वकर्मा महामंत्री, सुरेश साहू महामंत्री ,सावित्री वर्मा अध्यक्ष महिला मोर्चा, ज्ञानेश्वर वर्मा महामंत्री ,कपर्ण देवांगन सदस्य,राजेश्वरी साहू सदस्य , ओमेश्वरी पटेल दिव्या सिन्हा सदस्य ,आरती धीवर सदस्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता,समाज प्रमुख ,स्थानीय जनप्रतिनिधि ,बड़ी संख्या में देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है, मानव बुद्धि का विकल्प नहीं : डेका



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका आज डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ तकनीक भी निरंतर अतिव्रिस्त हो रही है। ऐसे समय में तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए होना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो चिकित्सा, कृषि, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में मानव की सहायक बन सकती है, लेकिन यह मानव बुद्धि, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का स्थान नहीं ले सकती। तकनीक को जीवन में सहायक के रूप में अपनाया जाना चाहिए न कि उसे किसी खतरे के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एआई और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज

हित के कार्यों में करें। अपने संबोधन में उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। डिजिटल एडिक्शन न हो यह कोशिश करनी चाहिए। आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग राज्यपाल ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास सदैव नवाचार और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हुआ है। जिस प्रकार अग्नि की खोज ने मानव जीवन को नई दिशा दी, उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान और तकनीक भविष्य के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग है।

देवपुरी में अवैध प्लांटिंग पर नगर निगम का बुलडोजर



रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध प्लांटिंग और कॉलोनियों के विकास के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में नगर निगम की जोन-10 टीम ने देवपुरी क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरुम सड़क को बुलडोजर से काट दिया और मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार देवपुरी स्थित वर्धमान नगर के पीछे लगभग एक एकड़ भूमि पर बिना अनुमति प्लांटिंग कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। संबंधित भूमि पर सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य

भी किए जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद नगर निगम के जोन-10 नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई शुरू की। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि पर किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति लिए बिना प्लॉट काटने और जमीन की बिक्री की तैयारी की जा रही थी। अवैध प्लांटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई मुरुम सड़क को निगम की टीम ने थ्री-डो मशीन की सहायता से काट दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के आगे के विकास कार्यों को रोकना और जमीन की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना था। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर रखी भवन निर्माण सामग्री को भी जब्त किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने 5 गांवों में लगाई चौपाल, सुझावों को गंभीरता से सुना

- ज्योति कलश भवन, सामुदायिक भवन एवं खाद्यान्न भंडारण भवन का किया लोकार्पण
- 56 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की, युवाओं को दिए क्रिकेट किट



रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी के खेकतरा, कुम्हारीली, मोहतरा कुर्मी, पीपरखुंटा और औराबांधा में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने इन गांवों में 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने जनचौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनके सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार और साय

सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने गांववालों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। उप मुख्यमंत्री साव ने खेकतरा में महामाया मंदिर में ज्योति कलश भवन का लोकार्पण कर

ग्रामवासियों को समर्पित किया। उन्होंने औराबांधा में नवनिर्मित सामुदायिक भवन एवं खाद्यान्न भंडारण भवन का लोकार्पण किया। श्री साव ने पांचों गांवों के युवाओं को क्रिकेट किट भी प्रदान किया। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

छोटे नेताओं की बलि देकर बड़े चेहरों के अपराधों पर पर्दा डाल रही कांग्रेस: कोठारी

रायपुर। भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक मितुल कोठारी ने कोण्डगाँव मामले में कांग्रेस द्वारा की गई कार्रवाई को महज एक राजनीतिक ढोंग और जनता की आंखों में धूल झाँकने का प्रयास बताया है। श्री कोठारी ने कहा कि कोण्डगाँव में अपराधिक मामला दर्ज होते ही कांग्रेस ने अपने छोटे नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है! श्री कोठारी ने पार्टी के सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव और कवासी लखमा जैसे नेताओं पर फैसला कब होगा? पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर सीडी कांड, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और कथित फर्जीवाड़े जैसे अलतंत गंभीर आरोप हैं। विधायक यादव पर बलौदाबाजार हिंसा मामले में दंगा भड़काने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संगीन आरोप दर्ज हैं। पूर्व मंत्री लखमा पर छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से खोखला करने वाले शराब घोटाले में संलिप्तता का गंभीर आरोप है।

मंत्रों के वाचन की अनिवार्यता संविधान के खिलाफ : शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार स्कूलों को आरएसएस की शाखा में परिवर्तित करना चाह रही। भाजपा सरकार द्वारा स्कूलों में सुबह दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, मध्यान्ह में भोजन मंत्र, शाम को छुट्टी होने पर गायत्री मंत्र एवं शांति मंत्र का वाचन बच्चों से कराया जाना संविधान के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 28(1) का संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) के तहत पूर्णतः राज्य-निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार

की धार्मिक शिक्षा या विशिष्ट धार्मिक प्रार्थना आयोजित नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 28(3) एवं धार्मिक स्वतंत्रता-राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में किसी भी छात्र को उसकी या उसके अभिभावकों की सहमति के बिना किसी धार्मिक प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आदेश में “आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें” शब्दावली से इसे अनिवार्य बनाने का आभास होता है, जो छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अल्पसंख्यक एवं अन्य समुदाय: शासकीय और अर्ध-शासकीय शालाओं में विभिन्न धर्मों, पंथों और पृष्ठभूमि के छात्र अध्ययनरत हैं।

16वें वित्त आयोग का दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

रायपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 16वें वित्त आयोग के निर्देशों के अनुरूप पंचायत विकास योजना एवं पंचायत उन्नति सूचकांक विषय पर सरगुजा जिले के सभी जनपद सदस्यों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। यह प्रशिक्षण 9 जून से 16 जून 2026 तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, सरगुजा के सभाकक्ष में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन सत्रों में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण, पंचायत उन्नति सूचकांक के विभिन्न संकेतकों, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पीएआई पोर्टल तथा 16वें वित्त आयोग के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की गई। प्रशिक्षण में पीटीसी की प्राचार्य डॉ. स्वेच्छा सिंह, अनुदेशक श्रीमती श्रद्धा मिश्रा एवं श्री उमेश प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विषय विशेषज्ञ के रूप में सहभागिता करते हुए महत्वपूर्ण जानकारीयां साझा कीं। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों की टीएमपी पोर्टल में प्रविष्टि एवं आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनपद सदस्यों की क्षमता वृद्धि करते हुए पंचायतों में योजनाबद्ध, सहभागी एवं प्रभावी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।

सामाजिक कुरीति के खिलाफ सक्षम कानून बने: डॉ. मिश्र

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि,हमारे यहाँ सामाजिकऔर जातिगत स्तर पर सक्रिय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों जशपुर में 1 परिवार



,कोंडागांव में 1परिवार,तथा केशकाल में10 परिवारों ,सरायपाली में 5 परिवारों, बगीचा कांसाबेल में 1 परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की घटना सामने आई है ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के मुखिया का क़हरना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों को सि्र झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है व उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो क़हर्हीं आर.टी.आई. लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार जैसी क़क्रुरीति के शिकार हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सामाजिक बहिष्कारजैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जनजागरण एवं प्रताड़ित लोगों की मदद के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्य कर रही है।

लोकभवन में कर्मियों के लिए एआई प्रशिक्षण सत्र आयोजित

रायपुर। लोकभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने तथा शासकीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Artificial Intelligence (AI) संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन अवर सचिव श्री अनुभव शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ,डू की कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावी इस्तेमाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रदान की गईं। सत्र में एआई के माध्यम से कार्यों को अधिक सरल, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक तकनीक की उपयोगी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यप्रणाली में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को डिजिटल दक्षताओं से सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, उप सचिव श्री श्रीनिधि साहू, श्री सुधीर सुलतानिया, श्री लक्षित त्रिलोक सेठिया श्री अनूप अग्रवाल एवं लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सब्सिडी, सौर ऊर्जा एवं राहत योजनाओं से अधिकांश उपभोक्ताओं को संरक्षण

बिजली दरों में संशोधन से आम उपभोक्ताओं पर न्यूनतम असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्युत टैरिफ के वार्षिक संशोधन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार को न्यूनतम रखने के लिए कई स्तरों पर राहत और संरक्षण की व्यवस्था की है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए औसतन 6.23 प्रतिशत अर्थात लगभग 42 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि स्वीकृत की गई है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना, बिजली बिल समाधान योजना और पीएम सूर्यधर योजना जैसी पहलों के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव काफी सीमित रहेगा।

निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। आयोग विद्युत कंपनियों की वार्षिक राज्यत्व आवश्यकता, उत्पादन लागत, कोयला, ट्रांसमिशन तथा वितरण व्यय सहित विभिन्न आर्थिक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा 26.5 लाख ऐसे उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इन राहतों के कारण लगभग 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं



पर बिजली दर वृद्धि का प्रभाव शून्य से लेकर मात्र 3.65 प्रतिशत तक ही होगा।

किसानों पर भार नहीं

राज्य के 8.65 लाख कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किए जाने के कारण किसानों पर इसका अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कृषि पंपों के स्थायी प्रभार को भी यथावत रखा गया है।

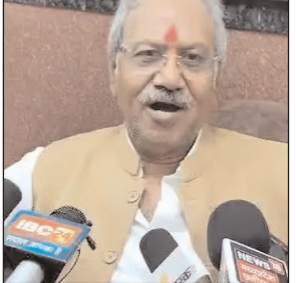
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्यधर योजना का

छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी से क्रियाबन्धन किया जा रहा है। अब तक लगभग 66 हजार उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से 16 हजार परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। वर्तमान में लगभग 89 हजार घरों में सौर संचयन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बिजली उपभोग की लागत में कमी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा 12 मार्च 2026 से मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में विशेष राहत प्रदान की जा रही है।

बृजमोहन ने ली कोर ग्रुप की बैठक

रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर जिला ग्रामीण भाजपा कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी अभियानों की कार्ययोजना और केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और राज्य सरकार के लोकलुभावन फैसलों ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। इन



उपलब्धियों को जन-जागरण अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। अग्रवाल ने उन्होंने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बूथ स्तर से

लेकर मंडल स्तर तक संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रायपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र में संगठन को एक नई ऊर्जा और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा ताकि केंद्र की राष्ट्रीय नीतियों और राज्य सरकार के जनसेवा कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में आगामी समय में चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों पर भी मंथन हुआ। अग्रवाल ने आह्वान किया कि वे जनसंपर्क अभियानों के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के विजन और राज्य सरकार के विकास कार्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर जनता के विश्वास को और अधिक पुख्ता करना है।